● वर्ष : 17 ● अंक : 236 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

दैनिक लोकतंत्र की शान

WWW.LKSTV.IN

लोकतंत्र का स्तंभ

दिल्ली से प्रकाशित

मंगलवार 16 जून 2026

भारत-स्लोवाकिया ने संबंधों को दिया 'व्यापक साझेदारी' का दर्जा

दोनों देशों के बीच 11 समझौते

एजेंसी। नई दिल्ली

भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को 'व्यापक साझेदारी' का दर्जा देने का फैसला किया है। दोनों देशों ने इसके अलावा आतंकवाद-विरोधी संयुक्त कार्य समूह और वाणिज्य दूतावास संवाद की स्थापना की भी घोषणा की है। दोनों देशों के बीच ब्रातिस्लावा में 11 समझौता ज्ञापन और आशय पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं। दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने वाला आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। कोसिसे तकनीकी विश्वविद्यालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में आईसीसीआर की पहली चेयर की स्थापित की जाएगी। श्रम प्रवासन, पर्यटन, विज्ञान, डिजिटल प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान, ऑडियो-विजुअल निर्माण, क्वांटम संचार और महत्वपूर्ण अवसंरचना संरक्षण, प्राकृतिक चिकित्सा और आयुष, छात्र विनिमय कार्यक्रम व छात्रवृत्तियों और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने सोमवार को ब्रातिस्लावा में आमने-सामने और प्रतिनिधिमंडल स्तर के प्रारूपों में बातचीत की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार एवं निवेश, रक्षा व सुरक्षा, टेक्नोलॉजी व इनोवेशन, अंतरिक्ष व परमाणु ऊर्जा, शिक्षा व संस्कृति और टैलेंट मोबिलिटी व लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। इनमें संयुक्त राष्ट्र में सुधार का मुद्दा भी शामिल था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार नेताओं ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐतिहासिक भारत-ईयू एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) के लागू होने से व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग, निवेश और रोज़गार पैदा करने के बड़े अवसर खुलेंगे। एक अहम कदम के तौर पर दोनों नेता भारत-स्लोवाकिया संबंधों को 'व्यापक साझेदारी' के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत को स्लोवाकिया द्वारा दी गई एकजुटता और समर्थन के लिए प्रधानमंत्री फिको को धन्यवाद दिया। यह आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों का मुकाबला करने के लिए दोनों देशों की दृढ़ प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। दोनों नेताओं ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। उन्होंने बहुपक्षवाद और वैश्विक शासन संस्थानों के सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री फिको ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में भोज का आयोजन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मेजबान को आपसी सहमति से तय की गई तारीख पर भारत आने का निमंत्रण दिया।

ब्रातिस्लावा में रोटी और नमक से हुआ मोदी का स्वागत

ब्रातिस्लावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस का अपना सफल दौरा पूरा करने के बाद अब स्लोवाकिया पहुंच गए हैं। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में भारतीय प्रधानमंत्री का बेहद भव्य और शानदार स्वागत किया गया। उल्लेखनीय है कि स्लोवाकिया के गठन के बाद वहां का दौरा करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री जुराज ब्लानार ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। इस दौरान पारंपरिक स्लोवाक रीति-रिवाज के अनुसार भारतीय प्रधानमंत्री को 'रोटी और नमक' भेंट किया गया, जिसे वहां की संस्कृति में परम सम्मान, सद्भावना और आतिथ्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। अपने इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा होगी। द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी 'टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर' स्मारक पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और शहीद सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा उनके सम्मान में डेन्यूब नदी पर एक विशेष हाई-टी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें वे शामिल होंगे।

ज्वलंत मुद्दा **संपादकीय**

पश्चिम बंगाल- तुम डार-डार हम पात-पात

संस्थाओं का निर्माण हुआ। उनकी जिम्मेदारी तय की गई, उनके लिए कानून बनाए गए। भारत के संविधान में विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में संविधान की शक्तियों में तीनों को अधिकार दिए गए। भारत का संविधान और लोकतंत्र, सनातन की आस्था और विश्वास जिसमें ब्रह्मा-विष्णु और महेश तीन महाशक्तियों को ब्रह्मांड को संचालित करने का आधार माना गया है। ठीक उसी तरह से भारत में उक्त तीनों स्तम्भ को ताकतवर बनाते हुए, चौथा स्तंभ मीडिया और जनता को बनाया गया। भारत के संविधान में जनता का राज कायम किया गया। जनता ही चुनाव के माध्यम से अपने अधिकार निर्वाचित प्रतिनिधि को सौंपती है।

जनता से चुने विधायक और सांसद के बहुमत के आधार पर मिले अधिकार से विधानसभा और संसद में कानून बनाए जाते हैं। सांसदों और विधायकों को जनता के प्रति जिम्मेदार बनाया गया। संसद और विधानसभा में जनता का पक्ष रखने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। यह सारी व्यवस्था समय के साथ 1990 तक देखने को मिली। उसके बाद से गठबंधन की सरकारें बनने लगीं, सरकार बनाने के लिए जोड़-तोड़ होने लगा। विचारधारा एवं राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र का कोई महत्व नहीं रहा। उसके बाद से संवैधानिक व्यवस्था में लोकतंत्र कमजोर होना शुरू हुआ। अब इतना कमजोर हो गया है, कि इसे लोकतंत्र के स्थान पर ठोकतंत्र कहना शायद ज्यादा उपयुक्त होगा।

हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनाव हुए हैं। एसआईआर में 90 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। 27 लाख मतदाताओं ने ट्रिब्यूनल में अपील की। फैसला हुए बिना पश्चिम बंगाल का चुनाव हो गया। 2 लाख से ज्यादा अर्धसैनिक बल पश्चिम बंगाल के चुनाव में तैनात किए गए। मतदान और मतगणना को लेकर टीएमसी ने गड़बड़ियों की शिकायत चुनाव आयोग, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में की। किंतु समय रहते कोई फैसला नहीं हुआ। फार्म 17सी में ईवीएम मशीन के जो नंबर दर्ज थे, उनके स्थान पर अन्य ईवीएम मशीन से मतगणना की गई। आपत्ति करने पर मतगणना रोक दी गई, उसके बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए।

अब 4000 ईवीएम की मशीनें जल गई हैं। 45 दिन तक चुनाव आयोग को सारे सबूत सुरक्षित रखने होते हैं। अब सबूत जलने शुरू हो गए हैं। इसी बीच टीएमसी के सांसदों और विधायकों को सड़क पर पीटा गया। पश्चिम बंगाल में दहशत का वातावरण बना हुआ है। इसी बीच चर्चा है, 20 से अधिक सांसद टीएमसी छोड़कर एक अलग गुट बनाकर ऐसी पार्टी में जा रहे हैं, जिसका ना तो एक विधायक है, ना उसके सांसद हैं। त्रिपुरा में उसने कुछ चुनाव जरूर लड़े हैं। एक फ़ीसदी वोट भी उसे हासिल नहीं हुए हैं। ऐसी गुमनाम पार्टी में राष्ट्रीय पार्टी के सांसद और विधायक विलय करने जा रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा के अध्यक्ष इन्हें अनुमति प्रदान कर रहे हैं। आगे चलकर चुनाव आयोग से भी इन्हें मान्यता मिल जाएगी।

सैयद जकी हैदर | सम्पादक/प्रकाशक
MOBE NO.**9911371802**
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER**786**@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुई पहली व्यावसायिक उड़ान सेवा शुरु

नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सोमवार को औपचारिक रूप से उड़ान सेवाओं की शुरुआत हो गई। इस अवसर को प्रदेश के विकास के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। उद्घाटन के मौके पर यूपी सरकार के मंत्री बृजेश सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी के नेतृत्व में राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि करीब दो महीने पहले पीएम ने इस एयरपोर्ट का लोकार्पण किया था और आज यहां से पहली व्यावसायिक उड़ान लखनऊ के लिए हुई। उन्होंने बताया कि इस विशेष अवसर पर क्षेत्र के स्थानीय विधायक और 150 से ज्यादा किसान इस पहली उड़ान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह एयरपोर्ट केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं है, बल्कि यह पीएम मोदी के विजन और सीएम योगी की प्रभावी कार्यान्वयन नीति का प्रमाण है। साथ ही, यह उन किसानों के सहयोग और त्याग का प्रतीक भी है, जिन्होंने इस परियोजना के लिए अपनी भूमि सरकार को दी। मंत्री बृजेश सिंह ने किसानों के योगदान को सराहते हुए कहा कि आज के दिन सबसे ज्यादा बधाई के हकदार किसान हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिंह ने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन से एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास होगा।

नीट पुनर्परीक्षा के लिए चार लाख अभ्यर्थियों ने डाउनलोड किए प्रवेश पत्र

नई दिल्ली। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने कहा है कि 21 जून को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2026 पुनर्परीक्षा के लिए अब तक लगभग 4 लाख अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) डाउनलोड कर चुके हैं। हालांकि कुछ उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के दौरान तकनीकी गड़बड़ियों और सर्वर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें दूर करने के लिए एजेंसी की टीमें लगातार काम कर रही हैं। एनटीए ने सोमवार को एक बयान में कहा कि उसे उन समस्याओं की जानकारी है जिनका सामना कुछ छात्रों को एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग के दौरान करना पड़ा है। एजेंसी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी उम्मीदवार अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। एनटीए ने अभ्यर्थियों को हुई असुविधा के लिए खेद भी व्यक्त किया। इससे पहले रविवार देर रात एनटीए ने जानकारी दी थी कि करीब एक लाख उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। एजेंसी ने यह भी बताया कि छात्रों के हित में शुल्क वापसी के लिए बैंक खाते का सत्यापन करने की सुविधा शुरू की गई है, जिसे दो-स्तरीय प्रमाणीकरण (टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन) लॉगिन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। एनटीए के अनुसार वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक के कारण सर्वर पर दबाव बढ़ा है लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं कि सभी अभ्यर्थी बिना किसी परेशानी के अपने प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकें। इस बीच कई उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर दो-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया और तकनीकी दिक्कतों को लेकर नाराजगी जताई है।

राष्ट्रपति मुर्मु ने पारंपरिक मिनिएचर कला शैलियों के कलाकारों से मुलाकात की

एजेंसी। नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रपति भवन में सोमवार को भारत की पारंपरिक मिनिएचर कला शैलियों के कलाकारों के एक समूह से मुलाकात की और उनके काम को देखा। राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार राष्ट्रपति भवन के 'आर्टिस्ट-इन-रेसिडेंस' कार्यक्रम के तहत वहां रह रहे 11 कलाकारों ने राजस्थानी जैसी अलग-अलग कला शैलियों का प्रदर्शन किया। इसी दौरान राष्ट्रपति मुर्मु ने आज इन कलाकारों से मुलाकात की और उनके काम को देखा। 'आर्टिस्ट-इन-रेसिडेंस' कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का जश्न है, जो सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने में जीवित कला परंपराओं की अहम भूमिका को फिर से रेखांकित करता है।

देश में पेट्रोल, डीजल और कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक, एलपीजी की सप्लाई स्थिरः सरकार

एजेंसी। नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई स्थिर बनी हुई है। पश्चिम एशिया संकट के बावजूद रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। साथ ही कच्चे तेल का स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में बनाए रखा जा रहा है। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर-मंत्रालयी पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस (एलपीजी सिलेंडर) की सप्लाई स्थिर बनी हुई है। रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में बनाए रखा जा रहा है। सुजाता शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि हालांकि, कुछ रिटेल आउटलेट्स पर बिक्री में असामान्य रूप से तेजी देखी जा रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि औद्योगिक, प्रत्यक्ष, संस्थागत और व्यावसायिक और कमर्शियल ग्राहकों ने अब रिटेल आउटलेट्स से ईंधन खरीदना शुरू कर दिया है, जिससे वहां बिक्री बढ़ गई है। मई में, 42 करोड़ डीजल की बिक्री बल्क से रिटेल आउटलेट्स पर शिफ्ट हो गई। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि एलएनजी कैरियर 'दिशा' 62,370 एमटी एलएनजी कार्गो लेकर होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित गुजर चुका है। उन्होंने कहा कि इस जहाज के 18 जून को दहेज पहुंचने की उम्मीद है। ओपेश कुमार शर्मा ने कहा कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, नाविकों की भलाई सुनिश्चित करने और उन्हें हर तरह की मदद देने के लिए विदेश मंत्रालय, विदेशों में भारतीय मिशनों, शिपिंग कंपनियों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ लगातार तालमेल बनाए हुए है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया में विगत 28 फरवरी से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच आज शांति समझौते पर सहमति बनी है।

अमेरिका-ईरान समझौते का प्रधानमंत्री ने किया स्वागत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए बनी सहमति का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के क्रियान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी तथा वैश्विक व्यापार और नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सकेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हुआ है और कई देशों में जनहानि भी हुई है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए बनी समझ का वह स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि शेष लंबित मुद्दों पर जारी वार्ता एक टिकाऊ और अंतिम समझौते तक पहुंचेगी, जिससे क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति स्थापित हो सके। प्रधानमंत्री मोदी की यह प्रतिक्रिया उस समय आई जब खबरें सामने आईं कि अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, रणनीतिक महत्व वाले होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता दोबारा शुरू करने के उद्देश्य से एक प्रारूप ढांचे पर सहमति बनाई है।

एलओसी पर पाक चौकी से की गई फायरिंग, सीजफायर का उल्लंघन!

पूंछ। जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर के तरकुंडी इलाके में पाकिस्तान की ओर से कथित तौर पर सीजफायर उल्लंघन किया गया है। बताया जा रहा है कि पाक चौकियों से करीब 8 मिनट तक रुक-रुक कर फायरिंग की गई। सूत्रों के मुताबिक घटना के बाद सीमा पर सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं और पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। फिलहाल किसी तरह के जान-माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। भारतीय सेना या संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की ओर से अभी तक इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट में सीमा से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि यदि सीजफायर उल्लंघन की पुष्टि होती है तो यह हाल के दिनों में नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ने का एक और मामला माना जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रही हैं और स्थानीय स्तर पर भी सतर्कता बढ़ा दी है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से मामले की पुष्टि नहीं की गई है।

अमेरिकी में सुंदर पिचाई के खिलाफ लगे नारे भाषण के बीच छात्रों ने किया वॉकआउट

एजेंसी। वाशिंगटन

अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कार्यक्रम में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई अपना भाषण शुरू करने वाले थे कि कुछ छात्रों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद ही उत्साह का माहौल तनाव में बदल गया। खबरें हैं कि कुछ छात्रों ने वॉक आउट भी कर दिया, जिसके कारण कार्यक्रम खासा प्रभावित हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिचाई मंच पर पहुंचे और अपना भाषण शुरू करने वाले थे। इसके साथ ही छात्रों ने भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और शोर मचाने लगे। खबर है कि कुछ छात्र नारेबाजी करते हुए मैदान छोड़कर भी बाहर चले गए। हालांकि, सिर्फ पिचाई ही नहीं, बल्कि कार्यक्रम में शामिल कई मेहमानों को अपने भाषण के दौरान ऐसे विरोध का सामना करना पड़ा। खबरें हैं कि छात्र इजराइली सरकार के साथ गूगल के कॉन्ट्रेक्ट का विरोध कर रहे थे। कुछ छात्र फ्री पैलेस्टीन का नारा भी लगा रहे थे। दरअसल, यह विरोध प्रोजेक्ट निम्बस को लेकर बताया जा रहा है। जबकि, पिचाई ने अपने भाषण में एआई का जिक्र भी नहीं किया और उन्हें छात्रों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। खास बात है कि पिचाई भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ही छात्र रह चुके हैं। 1.2 बिलियन डॉलर का यह प्रोजेक्ट क्लाउड कम्प्यूटिंग और एआई से जुड़ा हुआ है। इजराइली सरकार ने यह प्रोजेक्ट गूगल और अमेजन को दिया है।

सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी

एजेंसी। हरिद्वार

सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में आस्था का नजारा देखने को मिला। सुबह से ही हर की पौड़ी समेत गंगा के प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना की। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। जिलाधिकारी और एसएसपी ने खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी ने बताया कि करीब तीन सौ साल बाद ऐसा दुर्लभ योग बना है। ग्रहों की वर्तमान स्थिति, समवर्ती अमावस्या और ज्यादा मास का यह संयोग बना है। यह अपने आप में विशेष है। हरिद्वार समेत प्रयागराज, सरयू तट और अन्य सभी तीर्थस्थलों के लिए इसका विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि जो लोग पूरे मास व्रत रखते हैं, उन्हें सोमवती अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों और पितरों का तर्पण करना चाहिए। जहां-जहां नदियां और संगम हैं, वहां स्नान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति घर पर ही है, तो वह स्नान के जल में थोड़ा-सा गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकता है और अपने पूर्वजों का स्मरण कर सकता है। अमावस्या के दिन पितृ-तर्पण का विशेष महत्व माना जाता है। अपने पितरों की मुक्ति और कल्याण के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह शुभ और सुलभ योग है। रिपोर्ट के मुताबिक पुरी ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ (पीपल) हूं, देवर्षियों में नारद हूं, सिद्धों में कपिल मुनि हूं और गंधर्वों में चित्ररथ हूं। इसलिए संसार के समस्त वृक्षों में पीपल का विशेष स्थान है। पीपल एक ऐसा वृक्ष माना जाता है जो चौबीसों घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसी कारण हमारे ऋषियों ने इसकी पूजा और संरक्षण की परंपरा स्थापित की। पीपल का अभिषेक कर उसे जल अर्पित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सोमवती अमावस्या के दिन सर्वप्रथम गंगा स्नान करना चाहिए और उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जिलाधिकारी ने बताया कि सोमवती अमावस्या का स्नान जारी है।

भारतीय अर्थव्यवस्था का संकट जल्द दूर होने वाला नहीं

नई दिल्ली। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते की खबरों के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फैसले का स्वागत कर उम्मीद जाहिर की कि अमेरिका, ईरान और इजरायल तीनों देश समझौते का पालन करे, भले ही पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक न हुई हो। कांग्रेस नेता रमेश ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के बिना किसी प्रतिबंध के फिर से खुलने से भारत को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका अर्थ यह नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद संकट जल्द ही दूर होगा। कांग्रेस नेता ने तर्क दिया कि ये समस्याएं पश्चिम एशिया में मौजूदा युद्ध से पहले की हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के सिर्फ दो दिन बाद शुरू हुआ था। उन्होंने बताया कि रुपया लंबे समय से दबाव में है और डॉलर की मांग-आपूर्ति में अंतर बढ़ रहा है। कांग्रेस महासचिव ने मोदी सरकार पर निशाना साधकर कहा कि बीते एक दशक में निवेश की दर सुस्त रही है और वास्तविक मजदूरी में ठहराव आ गया है।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEUTICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

संक्षिप्त समाचार

शॉर्ट सर्किट से अस्पताल में लगी आग, समय रहते बुझाई गई

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के सागरपुर इलाके में स्थित एएस मल्टी किडनी अस्पताल में रविवार देर रात आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। हालांकि अस्पताल कर्मचारियों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के चलते आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस के अनुसार, रविवार रात करीब 10:27 बजे सागरपुर थाना पुलिस को पीसीआर कॉल के माध्यम से डाबड़ी-पालम रोड स्थित एएस मल्टी किडनी अस्पताल में आग लगने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में करीब 15 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। साथ ही पीसीआर, दमकल विभाग और सीएटीएस एंबुलेंस की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि अस्पताल कर्मियों ने अग्निशमन यंत्रों की मदद से आग पर पहले ही काबू पा लिया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बिजली के मीटर और पैनल में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी थी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की तीन गाड़ियां और बीएसईएस की टीम भी मौके पर पहुंची। अस्पताल के पिछले हिस्से में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी आगे आकर अस्पताल स्टाफ की मदद की। घटना के समय अस्पताल में करीब 10 से 15 मरीज मौजूद थे। अस्पताल प्रशासन ने सभी मरीजों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। पुलिस ने बताया कि आग लगने की इस घटना में किसी के घायल होने या किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है।

वायरल वीडियो की जांच में खुलासा: बच्चे पर पानी डालने वाला व्यक्ति निकला पिता, मानसिक तनाव से गुजर रहा

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर एक बच्चे पर पानी डालने का वीडियो वायरल होने के बाद पश्चिमी जिला पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में सामने आया कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति बच्चे का पिता है, जो हाल ही में हुए वैवाहिक विवाद और तलाक के बाद मानसिक तनाव से गुजर रहा है। पुलिस ने बताया कि बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है और उसे उसकी मां को सौंप दिया गया है। पश्चिमी जिला पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामले की तत्काल जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पता चला कि वीडियो में दिखाई दे रहा व्यक्ति रघुबीर नगर निवासी अरुण (30) है, जो बच्चे का पिता है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि अरुण हाल ही में हुए वैवाहिक विवाद और तलाक के बाद से व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहा है। उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए परिवार के सदस्यों ने उसे उपचार और देखभाल के लिए एक पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया है। पुलिस ने बताया कि घटना के समय बच्चे को किसी तरह की शारीरिक क्षति नहीं पहुंची। जांच के दौरान बच्चा सुरक्षित मिला और परिजनों ने उसे उसकी मां के सुपुर्द कर दिया है। पश्चिमी जिला पुलिस ने बच्चे की मां से संपर्क किया है। अधिकारियों का कहना है कि थाने में शिकायत मिलने के बाद मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले वीडियो या संदेशों को बिना सत्यापन के साझा न करें। किसी भी संवेदनशील मामले में तथ्यों की पुष्टि होने तक अफवाहों से बचना चाहिए। उल्लेखनीय है कि वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर विभिन्न तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थीं। हालांकि, पुलिस की जांच में स्पष्ट हुआ है कि मामला पारिवारिक परिस्थितियों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।

केरल में महिलाओं के लिए शुरू हुई प्रियदर्शिनी निःशुल्क बस योजना, यूडीएफ सरकार की पहली इंदिरा गारंटी: वेणुगोपाल

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस ने केरल में सत्ता संभालने के एक महीने के भीतर ही यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने अपनी पहली इंदिरा गारंटी लागू कर दी है। लंबे समय से प्रतीक्षित प्रियदर्शिनी निःशुल्क बस योजना अब लागू हो चुकी है। वेणुगोपाल ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इस योजना के तहत केरल की महिलाएं केएसआरटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी और हर महीने हजारों रुपये की बचत कर पाएंगी। उन्होंने इसे जनहितकारी कदम बताते हुए कहा कि यूडीएफ हमेशा जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहा है और अपने वादों को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो या अब केरल यूडीएफ ने जनता के हित में ठोस कदम उठाए हैं। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी।

प्रवेश वर्मा ने एल.एम. बंध में बाढ़ नियंत्रण कक्ष का किया उद्घाटन, मानसून के लिए व्यवस्थाओं का लिया जायजा

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोमवार को शास्त्री नगर के एल.एम. बंध में बाढ़ नियंत्रण कक्ष का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने आने वाले मॉनसून के लिए तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली सरकार का काम मानसून के आने के साथ ही, राजधानी के लोगों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके बाद तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई।प्रवेश वर्मा ने बताया कि मानसून से पहले कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया है। 2023 में जो स्थिति देखी थी फिर से वैसी स्थिति न हो इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग और प्रशासन एक-एक व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि सभी एजेंसियों को लगातार सतर्क रहने और किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक तैयार शहर ही मुश्किलों का सामना करने में सक्षम होता है और मानसून के दौरान दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

ओडिशा में एक परिवार के सामाजिक बहिष्कार मामले का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में घटी एक अमानवीय घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। जिले के महुलदिहा गांव में एक परिवार को पिछले 12 सालों से कथित सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा था। इस बीच परिवार की एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु होने पर ग्रामीणों ने उनके अंतिम संस्कार में सहयोग देने से भी साफ इनकार कर दिया। आयोग ने सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विवाद करीब 12 साल पहले शुरू हुआ था। पीड़ित परिवार की बेटी कुछ समय के लिए दूसरी जाति के एक व्यक्ति के साथ घर से बाहर चली गई थी। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने परिवार पर भारी जुर्माना लगा दिया। परिवार बेहद गरीब था और जुर्माने की रकम चुकाने में असमर्थ था इसलिए ग्रामीणों ने पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया। खबर के मुताबिक, 12 वर्षों तक इस सामाजिक दंश को झेलने के बाद हाल ही में परिवार की बुजुर्ग महिला का निधन हो गया। ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार में बेटी या परिवार की मदद करने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों के इस अमानवीय रुख के बाद स्थानीय प्रशासन ने मामले में हस्तक्षेप किया। प्रशासन और कुछ स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग व सक्रिय प्रयासों से बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार संपन्न कराया जा सका।

बीमा पॉलिसी रिन्यूअल के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार आरोपित गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम जिला साइबर थाना पुलिस ने बीमा पॉलिसी रिन्यूअल के नाम पर लोगों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बनाने वाले एक संगठित साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो लाख रुपये नकद, 10 मोबाइल फोन, फर्जी बीमा दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान गांधी नगर निवासी सुनील कुमार रावत (38), राहुल (28), सोनू (37) और शिवम उर्फ मोनू (26) के रूप में हुई है। आरोपितों ने एक वरिष्ठ नागरिक को बीमा पॉलिसी रिन्यूअल का झांसा देकर चार लाख रुपये की ठगी की थी।दक्षिण-पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने सोमवार को बताया कि 18 मई 2026 को साइबर थाना दक्षिण-पश्चिम में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 308, 318(4), 319 और 340 के तहत ई-एफआईआर संख्या 235/26 दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उसे व्हाट्सएप कॉल के जरिए खुद को एक वित्तीय कंपनी का प्रतिनिधि बताने वाले व्यक्ति ने संपर्क किया।कॉलर ने शिकायतकर्ता से कहा कि उसकी बीमा पॉलिसी की अवधि समाप्त हो चुकी है और पॉलिसी को सक्रिय रखने के लिए चार लाख रुपये का प्रीमियम तुरंत जमा करना होगा। आरोपितों की बातों में आकर पीड़ित ने बताए गए बैंक खातों में चार लाख रुपये स्थानांतरित कर दिए। इसके बाद आरोपितों ने व्हाट्सएप पर फर्जी बीमा पॉलिसी दस्तावेज भेजकर उसे भरोसे में ले लिया।मामले की गंभीरता को देखते हुए इंस्पेक्टर कुलवीर सिंह के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया। जांच टीम ने मोबाइल नंबरों, डिजिटल फुटप्रिंट, बैंक खातों, वित्तीय लेनदेन और धन के प्रवाह का तकनीकी विश्लेषण किया। साथ ही स्थानीय खुफिया तंत्र और लगातार निगरानी के जरिए आरोपितों तक पहुंच बनाई गई। जांच के दौरान गांधी नगर से सुनील कुमार रावत को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से दो मोबाइल फोन, आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट और ठगी की रकम में से दो लाख रुपये नकद बरामद किए गए। पूछताछ में सुनील ने खुलासा किया कि राहुल फर्जी सिम कार्ड, बैंक खाते और नकली बीमा दस्तावेज उपलब्ध कराने का काम करता था।सुनील की निशानदेही पर राहुल और सोनू को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे फर्जी बैंक खातों की व्यवस्था करते थे, ठगी की रकम का बंटवारा करते थे और नकली बीमा पॉलिसी दस्तावेज तैयार कर पीड़ितों को भेजते थे। आगे की पूछताछ में राहुल ने खुलासा किया कि वारदात में इस्तेमाल किए गए फर्जी सिम कार्ड शिवम उर्फ मोनू उपलब्ध कराता था। इसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया।

ऐसे करते थे ठगी: पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपित बेहद सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देते थे। गिरोह के सदस्य फर्जी या अनजान लोगों के नाम पर हासिल किए गए सिम कार्ड का इस्तेमाल कर व्हाट्सएप कॉल करते थे और खुद को बीमा कंपनी का अधिकारी बताते थे। वे लोगों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों को यह कहकर डराते थे कि उनकी बीमा पॉलिसी समाप्त हो गई है और उसे तत्काल रिन्यू नहीं कराया गया तो पॉलिसी के लाभ बंद हो जाएंगे। इसके बाद वे पीड़ितों से प्रीमियम के नाम पर रकम फर्जी बैंक खातों में जमा करा लेते थे। भुगतान होने के बाद पीड़ितों को व्हाट्सएप पर फर्जी बीमा पॉलिसी दस्तावेज भेज दिए जाते थे, ताकि उन्हें किसी तरह का संदेह न हो। बाद में ठगी की रकम विभिन्न खातों से निकालकर गिरोह के सदस्यों में उनकी भूमिका के अनुसार बांट दी जाती थी।

आरोपितों की भूमिक- सुनील कुमार रावत (38) टेलीकॉलर और ठगी का मुख्य संचालक। वहीं राहुल (28) फर्जी बैंक खातों की व्यवस्था और रकम का बंटवारा करता था। जबकि सोनू (37) फर्जी बीमा दस्तावेज तैयार करना काम और शिवम उर्फ मोनू (26) फर्जी सिम कार्ड उपलब्ध कराता था। पुलिस आरोपितों के कब्जे से दो लाख रुपये नकद, तीन कीपैड मोबाइल फोन, सात एंड्रॉयड मोबाइल फोन, आपत्तिजनक व्हाट्सएप चैट और फर्जी बीमा पॉलिसी दस्तावेज बरामद किया है।

संगठन हमारा आधार ! सेवा हमारा संस्का

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली: दिल्ली प्रदेश के राष्ट्रीय लोकदल, महिला प्रकोष्ठ के नेतृत्व में दिल्ली स्थित 8 महादेव रोड़ में महिला सम्मेलन आदरणीय श्री त्रिलोक त्यागी जी, संगठन राष्ट्रीय महासचिव जी की गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।<आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष कमलेश मलिक जी ने की तथा संचालन प्रदेश महासचिव जैस्मिन जी एवं महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय महासचिव शालिनी सिंह जी ने किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इन्दिरा कपिलावे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग का आयोजक राष्ट्रीय सचिव सोनिका आनंद जी ने भव्य स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा ये आयोजन केवल एक माध्यम नहीं, बल्कि किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं की आवाज़ और वैचारिक संवाद का सशक्त मंच है। भारतीय संस्कृति में महिला सशक्तिकरण एवं उनके सम्मान से ही एक सशक्त और समृद्ध समाज का निर्माण संभव है, हमें यह समझना होगा कि नारी केवल उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि शक्ति का प्रतीक है। हमारा लक्ष्य है कि रालोद की जनहितैषी सोच, संघर्ष और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को पुनः गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाया जाए, तथा संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने का आह्वान किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से सहभागिता

- प्रबुद्ध कुमार जी, राष्ट्रीय सचिव
- मनीषा अहलावत जी, राष्ट्रीय सचिव
- रजनीश मलिक जी, प्रदेश अध्यक्ष
- मनमोहन जी, प्रदेश महासचिव
- निशा चौधरी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला विंग
- शोभा विरियाला जी, राष्ट्रीय महासचिव महिला विंग
- ऋचा सिंह जी, राष्ट्रीय महासचिव महिला विंग
- दीपमाला जी, प्रदेश उपाध्यक्ष यूपी महिला विंग एवं वरिष्ठ नेता, सम्मानित पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आदि गणमान्य महिला व्यक्तित्व उपस्थित रहे।

भारतीय रेलवे ने उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपये के कवच प्रोजेक्ट को मंजूरी दी

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के शेष ब्रॉड गेज मार्गों पर 'कवच' प्रणाली स्थापित करने की 201 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना 811 रूट किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगी। रेल मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि इस कार्य को भारतीय रेलवे के शेष मार्गों पर एलटीई आधारित संचार नेटवर्क के साथ 'कवच' प्रणाली उपलब्ध कराने के व्यापक कार्यक्रम के तहत स्वीकृति दी गई है।परियोजना के तहत अंबाला मंडल के कई महत्वपूर्ण रेलखंडों पर कवच प्रणाली स्थापित की जाएगी। इनमें अंबाला छावनी-लुधियाना, कालका-चंडीगढ़-न्यू मोरिंडा-साहनेवाल, सरहिंद-दौलतपुर चौक, राजपुरा-बठिंडा-श्रीगंगानगर तथा लुधियाना-धूरी-जाखल रेलखंड शामिल हैं।ये रेलमार्ग हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले प्रमुख कॉरिडोर हैं, जहां यात्री और माल यातायात का भारी दबाव रहता है। क्षेत्र में लोगों और वस्तुओं के आवागमन में इन मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है।उल्लेखनीय है कि 'कवच' भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली सिग्नल पासिंग एट डेंजर (एसपीएडी) जैसी घटनाओं को रोकने, आवश्यकता पड़ने पर स्वतः ब्रेक लगाने, संवेदनशील परिस्थितियों में ट्रेन की गति नियंत्रित करने और टक्कर की आशंका को काफी हद तक कम करने में सक्षम है।रेलवे का कहना है कि नेटवर्क पर सुरक्षा, विश्वसनीयता और परिचालन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च घनत्व और रणनीतिक महत्व वाले मार्गों पर 'कवच' प्रणाली का विस्तार लगातार किया जा रहा है। अंबाला मंडल की यह परियोजना उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

उच्च स्तरीय शिक्षा योजना के तहत 4,742 वंचित छात्र लाभ पा सके

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार की उच्च स्तरीय शिक्षा योजना के तहत पेशेवर, शोधकर्ता और उद्यमी देश के विकास कार्यों को गति दे रहे हैं। यह योजना अनुसूचित जाति (एससी) के लिए है। अब तक 4,742 वंचित छात्र इस योजना का लाभ पा चुके हैं। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार सरकार का लक्ष्य यह है कि एससी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और सशक्त बनें। उन छात्रों के भी योगदान से राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल और आत्मनिर्भर बनेगा। इसमें नवप्रवर्तक और नेता भी शामिल हैं। इस योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिल सकता है जिनके परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपये है। इन समुदाय के मेधावी छात्रों को उच्च संस्थानों में निशुल्क प्रवेश दिया जाता है। इन संस्थानों में छात्रों को अनुसंधान और नवाचार करने का अवसर प्राप्त होता है। इनके योगदान, लगन और मेहनत से राष्ट्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनता है। फिलहाल, इस योजना के तहत छात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) जैसे प्रमुख प्रबंधन संस्थानों और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों सहित प्रमुख संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मंत्रालय के मुताबिक, यह योजना केन्द्र सरकार की शैक्षिक सशक्तिकरण, समावेशन और समान अवसर के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।उल्लेखनीय है कि इस योजना को 2007-08 में शुरू किया गया था। अब तक 4,742 छात्र इस योजना का लाभ पा चुके हैं। छात्रों पर खर्च होने वाला वार्षिक व्यय 2.17 करोड़ रुपये से बढ़कर 117.19 करोड़ हो गया है।

सरकार विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए और कदम उठाएगी: सीतारमण

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार देश में और विदेशी पूंजी लाने के लिए और कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि बॉन्ड मार्केट के लिए घोषित उपाय तो बस शुरुआत भर थे। सीतारमण ने नई दिल्ली में 'हीरो माइंडमाइन समिट 2026' को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, "हम मानते हैं कि हमें और विदेशी पूंजी की जरूरत है।" वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के घोषित उपाय महज शुरुआत हैं, जबकि अभी आगे और कदम उठाए जा सकते हैं।'हीरो माइंडमाइन समिट 2026' को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर ब्याज और पूंजीगत लाभ कर से छूट जैसे उपाय विदेशी पूंजी को वापस आकर्षित करने की दिशा में पहला कदम हैं। सीतारमण ने कहा, ''यह कहानी का अंत नहीं है और कदम उठाए जाएंगे। हम मानते हैं कि हमें और अधिक विदेशी पूंजी की आवश्यकता है।''सीतारमण ने 'माइंडमाइन समिट 2026' में हीरो एंटरप्राइज़ के चेयरमैन सुनील कांत मुंजाल और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज़ लिमिटेड के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल के साथ एक अनौपचारिक बातचीत (फायरसाइड चैट) में हिस्सा लिया। इस दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्थिति हर सप्ताह बदल रही है और नई-नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। इसलिए देश को हर ऐसी आपात स्थिति के लिए तैयार रहना होगा।उन्होंने कहा कि आरबीआई द्वारा घोषित ढांचे के तहत मुद्रा जोखिम की लागत आरबीआई वहन करेगा, जिससे बैंक बिना बाधा अपने संसाधन जुटा सकेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था कच्चे माल, कच्चे तेल और उर्वरकों के आयात के कारण ''गंभीर दबाव'' का सामना कर रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि सक्रिय नीतियों और राज्यों की मजबूत भागीदारी की वजह से भारत का डेटा सेंटर और जीसीसी इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है, जो गतिविधियां पहले बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली-एनसीआर तक ही सीमित थीं, वे अब तुमकुरु और मंगलुरु जैसे टियर-2 शहरों तक भी फैल रही हैं। इसका मतलब होगा ज़्यादा नौकरियां, बेहतर डेटा सुरक्षा और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने 5 जून को बैंकों को तीन से पांच वर्ष की अवधि वाले विदेशी मुद्रा गैर-निवासी (बैंक) जमा के लिए अपनी मुद्रा अदला-बदली सुविधा का उपयोग करने की अनुमति दी थी, जिससे वे अमेरिकी यूएस डॉलर जमा को आरबीआई के साथ बदल सकें एवं मुद्रा जोखिम का प्रबंधन कर सकें।

अमेरिकी सेना के हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से की चुप्पी तोड़ने की मांग

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली: ओमान की खाड़ी में एक जहाज पर अमेरिकी सेना के हमले में तीन भारतीय नाविकों की मौत को लेकर कांग्रेस ने मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुप्पी तोड़ें, राष्ट्र को संबोधित करें और शोक संतप्त परिवारों से स्वयं बात कर उन्हें न्याय का आश्वासन दें। पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार अमेरिका के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए उसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहे; साथ ही प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने और क्षेत्र में कार्यरत सभी भारतीय नाविकों की सुरक्षा की गारंटी की मांग भी करे। कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने यह मांग भी की कि समुद्री क्षेत्रों और संघर्ष वाले इलाकों में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था की तुरंत व्यापक समीक्षा हो और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्वदेश वापस लाया जाए। इसके अलावा उन्होंने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत की विदेश नीति की विफलता पर संसद में चर्चा कराए जाने की भी मांग की। उन्होंने इस हमले में जान गंवाने वाले आदित्य शर्मा (हिमाचल प्रदेश), शिवानंद चौरसिया (उत्तर प्रदेश) और पटनाला सुरेश (आंध्र प्रदेश) को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बेहद संवेदनशील मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं और उनका यह कायराना रवैया विफल विदेश नीति का जीता जागता सबूत है।

आयुर्वेद की तिगलारी और कन्नड़ पांडुलिपियों को बचाने की पहल शुरू

लोकतंत्र की शान

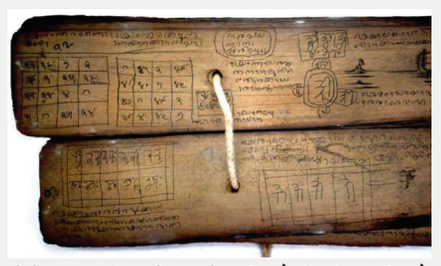

नई दिल्ली। भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान-संपदा को सुरक्षित रखने की पहल शुरू हुई है। इसके तहत तिगलारी और पुरानी कन्नड़ लिपि में लिखी गई आयुर्वेद की दुर्लभ पांडुलिपियों को पढ़ना और उन्हें आधुनिक लिपि में बदलने का काम शुरू किया गया है। इस दिशा में आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान केंद्रीय परिषद (सीसीआरएएस)औरकेंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से श्री वादीराजा रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग 15 दिनों का कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला का उद्देश्य उन प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों को संरक्षित करना है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञ युवा शोधार्थियों को इन पांडुलिपियों को पढ़ने, समझने और प्रकाशन के लिए तैयार करने में मदद करेंगे। सोमवार को सीसीआरएएस के महानिदेशक प्रो. वैद्य रबिनारायण आचार्य ने मीडिया को बताया कि भारत सरकार देश की पारंपरिक ज्ञान विरासत को सुरक्षित रखने और आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।कार्यशाला में तैयार की गई पांडुलिपियों को बाद में प्रकाशित किया जाएगा, ताकि आयुर्वेद से जुड़ा यह बहुमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।उल्लेखनीय है कि तिगलारी और पुरानी कन्नड़ लिपियों में लिखी आयुर्वेदिक पांडुलिपियों मुख्य रूप से कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सीसीआरएएस और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित यह तीसरी संयुक्त कार्यशाला है। इससे पहले ओडिशा के पुरी में करणी/देवनागरी लिपियों तथा केरल के वट्टेजुत्तु/मलयालम लिपियों पर केंद्रित कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं। कार्यशाला के दौरान तैयार किए गए लिप्यंतरित ग्रंथों को बाद में सीसीआरएएस और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, जिससे भारत की प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान-संपदा को संरक्षित करने और व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

संक्षिप्त समाचार

रामपुर में खेत में मिला युवक शव

» खंडिया चौराहे से 200 मीटर दूरी ग्रामीण ने देखा, फॉरेंसिक टीम ने जूटाऐ साक्ष्य

लोकतंत्र की शान : मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, रामपुर । उत्तर प्रदेश/ रामपुर के अज़ीम नगर थाना क्षेत्र में खंडिया चौराहे के पास एक खेत में सोमवार सुबह एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जहां शुरू की पुलिस ने शव के कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ग्रामीणों ने देखा युवक का शव जानकारी के अनुसार सुबह-सुबह करीब 8 बजे इंडिया चौराहे से लगभग 200 मीटर दूर बीऐल इंटर कॉलेज के निकट स्थित एक खेत में ग्रामीण ने युवक का शव

देख शव मिलने के एक खेत में ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, पुलिस जांच में मृतक की पहचान मनोज पुत्र धर्म सिंह 35 वर्ष है निवासी ग्राम दयानाथपुर थाना छल्लेट जनपद मुरादाबाद के रूप में हुई परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है परिजनों की दी घटना की सूचना,

घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम ने आवश्यक साक्ष्य-एकत्र किए और विभिन्न पहलवानों से जांच की घटना की सूचना मिलने पर क्षेत्राधिकारी टांडा कीर्ति निधि आनंद भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों से जानकारी ले आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है, और युवक की मौत के करण की वजह का सुराक निकल रही है फिलहाल युवक की मौत की किन परिस्थितियों में हुई यह स्पष्ट नहीं हो सका है पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के वास्तविक करणो का खुलासा हो सकेगा मामले की से जांच जारी है

एसपी कृष्ण कुमार के निर्देशन में सिरसी चौकी पुलिस का फ्लैग मार्च, पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की हुई सघन चेकिंग

अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था एवं आमजन में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए पुलिस ने बाजारों और प्रमुख स्थानों पर की फुट पेट्रोलिंग

लोकतंत्र की शान : सैय्यद कुमैल ज़ैदी , सम्भल/ सिरसी पुलिस अधीक्षक सम्भल श्री कृष्ण कुमार के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, कानून एवं शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र की सिरसी चौकी पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है। इसी क्रम में सिरसी चौकी प्रभारी फिरोज खान के नेतृत्व में कस्बा सिरसी के प्रमुख स्थानों, बाजारों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल गश्त (फुट पेट्रोलिंग) की गई तथा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। फुट पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस टीम ने बाजारों में घूमकर लोगों से संवाद स्थापित किया, व्यापारियों एवं स्थानीय नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को देने की अपील की। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर अनावश्यक रूप से घूमने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उनसे पूछताछ की गई और वाहनों की जांच कर आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। चौकी प्रभारी फिरोज खान ने कहा कि क्षेत्र में शांति, सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। असामाजिक तत्वों, अपराधियों एवं कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की नियमित गश्त एवं चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेंगे, ताकि आमजन स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सकें और क्षेत्र में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

हादसे में तड़प रहे बुजुर्ग के लिए फरिश्ता बने असगर अली अंसारी, अपनी कार से पहुंचाया अस्पताल

लोकतंत्र की शान : सैय्यद कुमैल ज़ैदी , सम्भल/ सिरसी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी ने मानवता और जनसेवा की मिसाल पेश करते हुए सड़क हादसे में घायल एक बुजुर्ग की मदद कर उन्हें समय रहते अस्पताल पहुंचाया। उनके इस मानवीय कार्य की क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है। जानकारी के अनुसार थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के नगर पंचायत सिरसी निवासी अबुजर पुत्र मोहसिन अपनी परचून की दुकान का सामान लेकर सम्भल से सिरसी वापस लौट रहे थे। जैसे ही वह सम्भल-मुरादाबाद रोड स्थित फूलसिंहा पुलिया के पास पहुंचे, पीछे से आ रहे एक अज्ञात ट्रैक्टर ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि अबुजर गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। इसी दौरान पीछे से गुजर रहे सपा जिलाध्यक्ष असगर अली अंसारी की नजर घायल बुजुर्ग पर पड़ी। उन्होंने तत्काल अपनी कार रुकवाई और बिना किसी देरी के घायल को अपनी कार में बैठाकर सिरसी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार कराया गया। बताया जाता है कि हादसे में अबुजर को कई चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलने पर 112 पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए स्कूटी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि आज के दौर में जब लोग सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों की मदद करने से बचते हैं, ऐसे समय में असगर अली अंसारी का यह कदम इंसानियत, संवेदनशीलता और जनसेवा का उत्कृष्ट उदाहरण है। लोगों ने उनके इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने एक जनप्रतिनिधि होने के साथ-साथ एक सच्चे इंसान होने का फर्ज भी बखूबी निभाया।

जिलाधिकारी,व पुलिस अधीक्षक, द्वारा विकास भवन, में आगामी मोहर्रम पर्व को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु पीस कमेटी की बैठ की गई

लोकतंत्र की शान : मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, रामपुर उत्तर प्रदेश /रामपुर/ जिलाधिकारी, अजय द्विवेदी एवं पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा, द्वारा विकास भवन, रामपुर में आगामी मोहर्रम पर्व को सकुशल, शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जनपद के विभिन्न समुदायों के धर्मगुरुओं, ताजियादारों, संभ्रांत नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित सभी धर्मगुरुओं एवं प्रतिनिधियों से आपसी भाईचारे, सामाजिक सौहार्द तथा शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए पर्व मनाने की अपील की गई एवं मोहर्रम के अवसर पर निकलने वाले जुलूस, अन्य धार्मिक आयोजनों को निर्धारित मार्ग एवं समय के अनुसार सम्पन्न कराया जाए, ताजियो की ऊचांई मानक अनुसार रखने तथा किसी भी प्रकार की नई परंपरा प्रारम्भ न करने तथा सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक, आपत्तिजनक अथवा अफवाह फैलाने वाली सामग्री का प्रसारण न करने आदि के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये। यदि किसी प्रकार की संदिग्ध सूचना प्राप्त होती है तो उसकी तत्काल सूचना स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन को दी जाए। जनप्रतिनिधियों एवं धर्मगुरुओं द्वारा दिए गए सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये । इस दौरान समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे ।

पौधारोपण कार्यक्रम में विधायक ने गिनाईं केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां

लोकतंत्र की शान संवाददाता सतीश चंद्र राणा

तहसील हसनपुर। हसनपुर / अमरोहा : केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे जनसंवाद एवं विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव भीमा ठीकरी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के अंतर्गत पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हसनपुर विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों तथा राष्ट्र निर्माण के संकल्पों की जानकारी दी। विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं व समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विधायक ने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्षों में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिनसे देश की आर्थिक,व सामाजिक स्थिति को मजबूती मिली है। उन्होंने लोगों से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने को कहा । इस मोके पर हसनपुर मंडल अध्यक्ष राजू राणा, वीडीओ हसनपुर विजय कुमार सक्सेना, प्रधान संघ अध्यक्ष यशपाल प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य देवेंद्र खड़गवंशी, नामित सभासद अजय पाल, मंडल महामंत्री सौरभ गुप्ता, मंडल महामंत्री प्रमोद पांडेय, मंडल उपाध्यक्ष भोजराम सिंह, ग्राम प्रधान भीमा ठीकरी राजवीर सिंह, ग्राम प्रधान सौंहत देशराज पाल, पूर्व ग्राम प्रधान अमर सिंह, बूथ अध्यक्ष गनेशी, चेतराम भगत, रामरतन सिंह, जगदीश डीलर सहित पार्टी कार्यकर्ता एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

चाइनीज मांझे ने फिर ली जानलेवा करवट गन्ना मंत्री के भतीजे की गर्दन कटी

बरेली में प्रतिबंधित मांझे का आतंक जारी, प्रशासन फिर हरकत में

लोकतंत्र की शान

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) बरेली शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का खतरा एक बार फिर गंभीर रूप में सामने आया है। सोमवार सुबह हुए एक दर्दनाक हादसे में प्रदेश के गन्ना मंत्री संजय सिंह गंगवार के भतीजे आदित्य गंगवार गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क पर फैले चाइनीज मांझे की चपेट में आने से उनकी गर्दन और चेहरे पर गहरे कट लग गए। घटना के बाद उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। यह हादसा उस समय हुआ जब आदित्य गंगवार रोजाना की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 6:30 से 7 बजे के बीच वह श्यामगंज पुल के पास पहुंचे ही थे कि सड़क पर फैला प्रतिबंधित चाइनीज मांझा अचानक उनकी गर्दन और चेहरे से टकरा गया। मांझा इतना तेज था कि कुछ ही क्षणों में उनकी गर्दन और चेहरे पर गंभीर चोटें आ गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा बेहद भयावह था। घायल होने के बाद भी आदित्य ने हिम्मत दिखाई और बिना घबराए स्वयं वाहन चलाकर ईशान हॉस्पिटल पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने तुरंत प्राथमिक उपचार शुरू किया और उनकी स्थिति पर निगरानी रखी गई। इस घटना के सामने आने के बाद शहर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन द्वारा समय-समय पर अभियान चलाए जाने के बावजूद बाजारों में प्रतिबंधित मांझा आसानी से उपलब्ध हो रहा है।

विकास ही विकास, जनता का विश्वास: चौधरी मुबाशिर अली खान पहुंचे कदम रसूल की जियारत, मरम्मत कार्य का लिया जायजा

लोकतंत्र की शान/ सैय्यद कुमैल ज़ैदी

संभल/ नगर पालिका परिषद क्षेत्र में वार्ड नं. 15 स्थित कदम रसूल की जियारत पर चल रहे मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण करने के लिए समाजसेवी एवं जनप्रतिनिधि चौधरी मुबाशिर अली खान और वार्ड सदस्य वकील अहमद पहुंचे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित लोगों को कार्य को समयबद्ध और बेहतर तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर चौधरी मुबाशिर अली खान ने कहा कि धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण और विकास उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। कदम रसूल की जियारत आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है, इसलिए यहां आने वाले जायरीनों और स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संभल में हर क्षेत्र में विकास कार्यों को गति दी जा रही है और जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप "विकास ही विकास, जनता का विश्वास" के संकल्प के साथ कार्य किया जा रहा है। वार्ड सदस्य वकील अहमद ने कहा कि जियारत के मरम्मत कार्य से न केवल धार्मिक स्थल की सुंदरता बढ़ेगी, बल्कि श्रद्धालुओं को भी बेहतर और स्वच्छ वातावरण मिलेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में जनहित और विकास से जुड़े कार्य निरंतर जारी रहेंगे। स्थानीय लोगों ने भी मरम्मत कार्य शुरू होने पर खुशी व्यक्त करते हुए चौधरी मुबाशिर अली खान और वकील अहमद के प्रयासों की सराहना की तथा उम्मीद जताई कि कार्य पूर्ण होने के बाद कदम रसूल की जियारत और अधिक भव्य एवं सुविधाजनक स्वरूप में दिखाई देगी। वार्ड नं. 15 स्थित कदम रसूल की जियारत पर चल रहे मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण करते चौधरी मुबाशिर अली खान एवं वार्ड सदस्य वकील अहमद

भारत राष्ट्रीय सेवक संघ की सभा में किसानों की समस्याओं पर हुई चर्चा संगठन विस्तार पर जोर

लोकतंत्र की शान संवाददाता सतीश चंद्र राणा

हसनपुर / अमरोहा भारत राष्ट्रीय सेवक संघ की एक महत्वपूर्ण सभा रविवार को हसनपुर तहसील क्षेत्र के गांव राजा नांगल स्थित सरस पैलेस में आयोजित की गई। सभा की अध्यक्षता नो सिंह ने की, जबकि संचालन निजाम प्रधान ने किया। सभा में संगठन के विस्तार, अनुशासन एवं संगठनात्मक नियमों के पालन पर विशेष बल दिया गया। साथ ही क्षेत्र के किसानों की विभिन्न समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया और उनके समाधान के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. विनोद नागर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के हितों से जुड़े कई मुद्दे लंबे समय से लंबित हैं। उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध, बिजली विभाग की लापरवाही पर भी सवाल उठाया किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किए जाने, खतौनी में अंशों के सही विभाजन, चकबंदी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा आवारा पशुओं द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाए जाने जैसी समस्याओं की चर्चा की उन्होंने कहा कि इन सभी मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार और संबंधित विभागों के समक्ष किसानों की आवाज मजबूती से उठाई जाएगी तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी वार्ता कर समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। सभा के दौरान संगठन विस्तार के तहत किसान यूनियन शंकर से जुड़े राजवीर सिंह को प्रदेश मीडिया प्रभारी तथा अशोक चौधरी को महिला मोर्चा का तहसील अध्यक्ष (अमरोहा) नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जिला अध्यक्ष दीपक गुर्जर रहे। इस मोके पर प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिंह, धीरज सिंह, मुनेश चंद्र, गंगानंद गिरी, चंद्रवीर सिंह, सतीश कुमार, नीरज यादव, नरसिंह, साहब सिंह, पीतम, हरकेश, हरसिल, पवन, कपिल, हर्षित, विनय, रमेश, अजय, जसवंत सिंह, विक्की चौहान, करण सिंह, होशियार सिंह, रघुवीर सिंह, शिवम चौहान, प्रशांत चौहान, वीर सिंह आदि लोग मौजूद रहे।

सिरसी ने देखा विकास का ऐतिहासिक क्षण, एक साथ 15 सड़कों के लोकार्पण से खिल उठे सभी वार्ड

» सिरसी में विकास का ऐतिहासिक दिनः एक साथ 15 सड़कों का लोकार्पण, दर्गाह हज़रत अब्बास (अ.स.) के सामने नाले का निर्माण

लोकतंत्र की शान/ सैय्यद कुमैल ज़ैदी

सम्भल/ सिरसी नगर पंचायत सिरसी के इतिहास में 15 जून का दिन विकास के स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया, जब नगर पंचायत चेयरमैन कौसर अब्बास ने एक ही दिन में सभी 15 वार्डों में नवनिर्मित 15 सड़कों का भव्य लोकार्पण कर नगरवासियों को ऐतिहासिक सौगात दी। इसके साथ ही दर्गाह हज़रत अब्बास (अ.स.) के सामने लंबे समय से चली आ रही जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए नाले का निर्माण भी कराया गया, जिससे क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। यह ऐतिहासिक विकास कार्य नगर पंचायत सिरसी के चहुंमुखी विकास की नई तस्वीर पेश कर रहा है। सभी वार्डों में सड़कों के निर्माण से लोगों को कीचड़, जलभराव और आवागमन की समस्याओं से राहत मिलेगी, जबकि नाले के निर्माण से दर्गाह क्षेत्र में जल निकासी व्यवस्था सुदृढ़ होगी। इस अवसर पर नगर पंचायत के सभी वार्डों के सभासद, सभासद प्रतिनिधि एवं नामित सभासद प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आदित्यवीर रस्तोगी, फरहत अब्बास, खुर्शीद अहमद, हाजी तसद्दुक अंसारी, कयामुद्दीन सैफी, साहिर किदवई, आशिक अब्बास, इनामुल हक कुरैशी, हबीब हैदर, इरफान हैदर, हाशिम अली, तोला (सभासद पति), अज़ीम कुरैशी (सभासद पति), भुकन सैनी (सभासद पति), मीसम अब्बास (सभासद प्रतिनिधि), वंदना वाल्मीकि, अनिल श्रीमाली और विजय गुप्ता सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर चेयरमैन कौसर अब्बास ने कहा, "सिरसी को एक आदर्श, स्वच्छ और सुंदर नगर बनाना ही हमारा एकमात्र संकल्प है। सभी 15 वार्डों में सड़कों का लोकार्पण और दर्गाह हज़रत अब्बास (अ.स.) के सामने नाले का निर्माण इसी विकास यात्रा का हिस्सा है। आने वाले समय में विकास की यह रफ्तार थमने वाली नहीं है और नगर के हर कोने तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।" नगरवासियों ने चेयरमैन कौसर अब्बास के इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बिना किसी भेदभाव के सभी 15 वार्डों में एक साथ विकास कार्य कराना उनके दूरदर्शी और जनहितकारी नेतृत्व का परिचायक है। 15 जून का यह दिन नगर पंचायत सिरसी के विकास इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में याद किया जाएगा।

12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में बरेली में योग सप्ताह का शुभारम्भ, 21 जून को होगा बृहद सामूहिक योगाभ्यास

लोकतंत्र की शान

(बरेली, उत्तर प्रदेश | संदीप चंद्रा) 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सोमवार को स्पोर्ट्स स्टेडियम, बरेली में योग सप्ताह का भव्य शुभारम्भ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश सरकार के मा० राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन विभाग डॉ० अरुण कुमार द्वारा भगवान धन्वंतरि एवं महर्षि पतंजलि के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन कर किया गया। योग सप्ताह का आयोजन जनपद में योग एवं स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह विशेष अभियान 15 जून से 20 जून 2026 तक संचालित होगा, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न योग गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सामूहिक योगाभ्यास, विभिन्न योगासन प्रस्तुतियां, स्लोगन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता तथा योग विषयक सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मा० मंत्री डॉ० अरुण कुमार ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जिसने पूरे विश्व में भारत की पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में तनावपूर्ण जीवनशैली और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के बीच योग न केवल शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है।

बसपा ने पूर्व मंडल प्रभारी पर की अनुशासनात्मक कार्रवाई, पार्टी से किया निष्कासित

लोकतंत्र की शान, संवाददाता सतीश चंद्र राणा

हसनपुर /अमरोहा। बहुजन समाज पार्टी की जिला कमेटी ने संगठनात्मक अनुशासन को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंडल जोन प्रभारी अजब सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी नेतृत्व ने उन पर संगठन की नीतियों के विपरीत गतिविधियों में शामिल होने तथा अनुशासनहीनता बरतने का आरोप लगाया है। जिला अध्यक्ष सोमपाल सिंह एडवोकेट द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि अजब सिंह के खिलाफ लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। मामले की समीक्षा के बाद संगठन हित में यह निर्णय लिया गया। आदेश के अनुसार उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है और किसी भी स्तर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला इकाई ने सभी कार्यकर्ताओं से संगठन की नीतियों एवं निर्देशों का पालन करने की अपील की है। बसपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि संगठन को मजबूत बनाने और अनुशासन बनाए रखने के लिए आगे भी आवश्यक कदम उठाए जाते रहेंगे।

अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है उर्स-ए-पाक: चौधरी मुदब्बिर अली खान

लोकतंत्र की शान/ सैय्यद कुमैल ज़ैदी

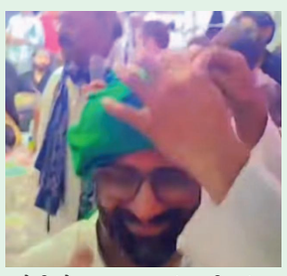

संभल। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में हज़रत दादा फकरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स-ए-पाक के अवसर पर मंडी किशन दास सराय में आयोजित दो अलग-अलग कार्यक्रमों में समाजसेवी एवं एआईएमआईएम नेता चौधरी मुदब्बिर अली खान ने अपने साथियों के साथ शिरकत की। इस दौरान उर्स कमेटी द्वारा उनकी दस्तारबंदी कर भव्य स्वागत एवं इस्तकबाल किया गया। पहले कार्यक्रम में चौधरी मुदब्बिर अली खान उर्स-ए-पाक में अपनी टीम के साथ हाज़िर हुए, जहां वसीम कुरैशी एवं उर्स कमेटी के पदाधिकारियों ने उन्हें दस्तार पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर चौधरी मुदब्बिर अली खान ने कहा कि उर्स-ए-पाक अमन, मोहब्बत, भाईचारे, इंसानियत और आपसी सौहार्द का पैगाम देता है। औलिया-ए-किराम की तालीमात हमें एक-दूसरे से प्रेम, जरूरतमंदों की मदद और समाज में एकता को मजबूत करने की सीख देती हैं। इसके उपरांत आयोजित दूसरे कार्यक्रम में चौधरी मुदब्बिर अली खान ने फीता काटकर उर्स-ए-पाक का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सूफी संतों की शिक्षाएं समाज को जोड़ने और नफरतों को मिटाकर इंसानियत की खिदमत का रास्ता दिखाती हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य हाफिज आमिर, वसीम कुरैशी, मरगूब, फहीम (आचार वाले), डॉ. ए.के. पठान, पठान साहब सहित उर्स कमेटी के सदस्य एवं बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे। उर्स कमेटी के पदाधिकारियों ने चौधरी मुदब्बिर अली खान के आगमन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि वह सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों में बढ़-चढ़कर भाग लेकर समाज में भाईचारे और एकजुटता को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। उनके आगमन से उर्स-ए-पाक की रौनक में और इज़ाफ़ा हुआ तथा उपस्थित लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।

संक्षिप्त समाचार

पत्नी की हत्या कर परिवार के साथ पति फरार, आत्मसमर्पण न करने पर घर पर चलेगा बुलडोजर

लोकतंत्र की शानः हाजीपुर। वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र के रजासन गांव में 16 अप्रैल 2026 को नवविवाहिता मोना कुमारी की हत्या कर शव गायब कर दिया गया था। इस मामले में पति, सास और ससुर समेत सभी आरोपी घर छोड़कर फरार हैं। पुलिस ने अब इन आरोपियों के खिलाफ इश्तेहार चिपकाए हैं। यह कार्रवाई न्यायालय से आदेश प्राप्त होने के बाद बिदुपुर थाना पुलिस द्वारा की गई है। पुलिस ने ढोल-नगाड़ों के साथ आरोपियों को जल्द से जल्द न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या गिरफ्तारी देने की हिदायत दी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के कारण उनमें असंतोष बढ़ रहा है। परिजनों के अनुसार, ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या कर शव को रात के अंधेरे में गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया था। इसके साथ ही, डेढ़ साल की बच्ची भी लापता बताई जा रही है। बिदुपुर थाना अध्यक्ष रवि प्रकाश ने बताया कि विवाहिता की हत्या और शव गायब करने के संबंध में थाना में कांड संख्या 186/26 दर्ज किया गया था। पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी, लेकिन वे फरार चल रहे थे। न्यायालय से आदेश मिलने के बाद इश्तेहार की कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि आरोपी न्यायालय में आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी नहीं देते हैं, तो उनके घरों की कुर्की-जब्ती की जाएगी।

आम से लदी पिकअप पलटी, फल लूटने का वीडियो वायरल, घायल दंपती तड़पते रहे, कारोबारी की मौत

लोकतंत्र की शानः मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र में आम से लदी एक पिकअप दुर्घटना का शिकार हो गई। इसके बाद घायल दंपती की मदद करने के बजाय लोग सड़क पर बिखरे आम बटोरने में जुट गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल आम कारोबारी की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही हैं। सुपौल के निर्मली थाना क्षेत्र निवासी 40 साल के अजय पासवान अपनी पत्नी संतरा देवी के साथ पश्चिम बंगाल से आम लादकर मुजफ्फरपुर आ रहे थे। शनिवार को गायघाट थाना क्षेत्र के हनुमान नगर चौक स्थित एनएच-27 पर उनकी पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए और वाहन में फंस गए। घटना का वीडियो आज वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक, हादसे के बाद पिकअप पर लदे आम सड़क पर बिखर गए। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन घायलों की मदद करने के बजाय आम उठाने और ले जाने में जुट गए। महिला और पुरुष दोनों सड़क पर बिखरे आम समेटते नजर आए, जबकि घायल दंपती दर्द से कराहते रहे। घटना की सूचना मिलने के बाद गायघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। अस्पताल में इलाज के दौरान अजय पासवान की मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी संतरा देवी की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज जारी है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दुर्घटना के बाद लोग आम लूटने में व्यस्त हैं, जबकि घायल सड़क पर पड़े हुए हैं। गायघाट थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि आम से लदी पिकअप के पलटने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान अजय पासवान की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है।

लॉकअप में युवक की पिटाई का मामला, पानापुर करियात के तत्कालीन थानाध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश

लोकतंत्र की शानः मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात थाने में युवक की कथित पिटाई और 70 हजार रुपए वसूली के मामले में मानवाधिकार आयोग ने एक्शन लिया है। तत्कालीन थानाध्यक्ष राजबल्लभ प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ-ही बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी, डीएम और एसएसपी मुजफ्फरपुर को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। सरैया थाना क्षेत्र के बहिलवारा रुपनाथ निवासी अमन कुमार को 11 मार्च 2025 को सुबह करीब 3 बजे तत्कालीन पानापुर करियात थानाध्यक्ष राजबल्लभ प्रसाद ने गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया था। जानकारी मिलने पर अमन के बहनोई रौशन प्रताप सिंह थाना पहुंचे थे। जहां पुलिस ने अमन कुमार को बंद कर रखा था। आरोप है कि थानाध्यक्ष ने छोड़ने के एवज में एक लाख रुपए की मांग की थी। जब रौशन प्रताप सिंह ने इसका विरोध किया तो आवेश में आकर थानाध्यक्ष ने उन्हें भी हाजत में बंद कर दिया था। मुंह, हाथ और पैर बांधकर उनके साथ काफी बेरहमी से मारपीट की गई थी। सूचना मिलने पर परिवार के सदस्य थाना पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि जब दोनों को छोड़ने का आग्रह किया तो तत्कालीन थानाध्यक्ष राजबल्लभ प्रसाद ने एक लाख रुपए की मांग रखी। 70 हजार रुपए लेने के बाद दोनों को छोड़ा गया। रौशन प्रताप सिंह की बाइक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसे लौटाने के एवज में 30 हजार रुपए की मांग अलग से की। मारपीट में गंभीर रूप से घायल रौशन को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कांटी में लाया गया। जहां से बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया था। इसके बाद मामला एनएचआरसी और बीएचआरसी के समक्ष पहुंचा। आयोग ने इसे मानवाधिकार का घोर उल्लंघन मानते हुए बिहार के मुख्य सचिव से पूछा है कि पीड़ित को क्यों नहीं एक लाख रूपए का मुआवजा दिया जाए। साथ-ही-साथ थानाध्यक्ष के खिलाफ अब तक प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की गई, इसपर भी आयोग की ओर से नाराजगी जाहिर की गई। आनन-फानन में पानापुर करियात थाना के थानाध्यक्ष द्वारा रविवार को रौशन की मां वीणा सिंह के नाम एक नोटिस जारी किया गया। 24 घंटे के अंदर थाना पर उपस्थित होकर आवेदन देने को कहा गया। रविवार शाम में ही वीणा सिंह के द्वारा पानापुर करियात थाना में तत्कालीन थानाध्यक्ष राजबल्लभ प्रसाद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने हेतु आवेदन दिया गया। मानवाधिकार मामलों के जानकार अधिवक्ता एस. के. झा ने बताया कि यह मामला सरकार की व्यवस्था का पोल खोल रही है। कारण कि एक प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पीड़ित परिवार को पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगानी पड़ी है। फिलहाल यह मामला एनएचआरसी और बीएचआरसी में चल रहा है। दोनों आयोगों के स्तर से पीड़ित परिवार को न्याय अवश्य मिलेगा, मुझे आयोग पर पूरा भरोसा है।

इटली में भारत का परचम लहराएंगे मुजफ्फरपुर के एहतेशाम

लोकतंत्र की शानः मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के एक साधारण परिवार से आने वाले मोहम्मद एहतेशाम रिजवी आने वाले 20 से 27 अगस्त तक इटली में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय, खड़ौना के 12वीं कक्षा के छात्र एहतेशाम का चयन अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड (आईईएसओ) के लिए भारतीय टीम में हुआ है। पूरे देश से सिर्फ चार छात्रों का चयन किया गया है, जिनमें मुजफ्फरपुर के एहतेशाम रिजवी भी शामिल हैं। एहतेशाम ने बताया कि उन्हें अर्थ साइंस ओलंपियाड के बारे में सबसे पहले स्कूल से जानकारी मिली। जवाहर नवोदय विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहती हैं, जिनमें वह नियमित रूप से हिस्सा लेते थे। इसी दौरान उनके फिजिक्स शिक्षक ने उन्हें अर्थ साइंस ओलंपियाड के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने आवेदन किया और प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर दी। 24 जनवरी 2026 को स्कूल स्तर पर परीक्षा आयोजित हुई थी। इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले पांच छात्रों का चयन अगले चरण के लिए किया गया। चयनित छात्रों को आगे की प्रक्रिया के लिए गुजरात के बड़ोदरा में आयोजित राष्ट्रीय प्रशिक्षण और मूल्यांकन शिविर में भेजा गया। एहतेशाम ने बताया कि बड़ोदरा में करीब 20 दिनों तक चले कैंप में कई तरह की शैक्षणिक और व्यावहारिक गतिविधियां आयोजित की गईं। इस दौरान प्रतिभागियों को पृथ्वी की संरचना, चट्टानों की परतों, भूगर्भीय संरचनाओं, वायुमंडल और पृथ्वी विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों की गहन जानकारी दी गई। कैंप में फील्ड वर्क, प्रैक्टिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा और वायवा भी लिया गया। सभी प्रतिभागियों को अलग-अलग विषय दिए गए थे। एहतेशाम का विषय "जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ" था, जिस पर उन्हें प्रस्तुति और मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। कई स्तरों की परीक्षा, प्रैक्टिकल और मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद देशभर से चार छात्रों का अंतिम चयन किया गया।

पटना कॉलेज से जेपी गोलंबर तक अभ्यर्थियों का मार्च

दरोगा मुख्य परीक्षा में धांधली का आरोप, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग

लोकतंत्र की शानः पटना

बिहार पुलिस में 1,799 दरोगा पदों के लिए 27 मई को आयोजित मुख्य लिखित परीक्षा में कथित पेपर लीक और धांधली के आरोपों को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र पटना कॉलेज परिसर से प्रदर्शन करते हुए जेपी गोलंबर तक मार्च निकाल रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र परीक्षा की निष्पक्ष जांच, कथित गड़बड़ियों की रिपोर्ट सार्वजनिक करने तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि परीक्षा से जुड़े कई तथ्यों और शिकायतों को लेकर उन्होंने विभिन्न सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों को आवेदन दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। छात्रों का आरोप है कि लगातार शिकायतों के बावजूद संबंधित एजेंसियों की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्हें सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है।

निष्पक्ष जांच और रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांगः अभ्यर्थियों ने मांग की है कि परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। उनका कहना है कि जब तक मामले की पारदर्शी जांच नहीं होगी, तब तक अभ्यर्थियों के मन में परीक्षा की विश्वसनीयता को लेकर सवाल बने रहेंगे।

गांधी मैदान के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षाः शहर में दरोगा अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट है। अभ्यर्थी गांधी मैदान से निकलकर जेपी गोलंबर तक मार्च करेंगे। इसको लेकर गांधी मैदान के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पटना पुलिस के ASP और SDPO रैंक के पुलिस पदाधिकारी जेपी गोलंबर पर मौजूद हैं। अभ्यर्थियों को रोकने के लिए मौके पर वाटर कैनन और एम्बुलेंस आदि बुलाई गई है।

पटना के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट की क्रॉस-इंस्पेक्शन मॉडल से होगी जांच

लोकतंत्र की शानः पटना

पटना नगर निगम ने विकास कार्यों की गुणवत्ता जांच करने के लिए क्रॉस-इंस्पेक्शन मॉडल अपनाने का निर्णय लिया है। इस उद्देश्य से निगम द्वारा 3 सदस्यीय कुल 6 विशेष जांच टीमों का गठन किया गया है। इन्हें नगर क्षेत्र के विभिन्न अंचलों में चल रहे 70 प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण कर डिटेल रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपा गया है। इस व्यवस्था के तहत किसी भी प्रमंडल के इंजीनियर अपने स्वयं के क्षेत्र में चल रहे परियोजनाओं का निरीक्षण नहीं करेंगे, बल्कि अन्य प्रमंडलों में संचालित विकास योजनाओं की गुणवत्ता की जांच करेंगे।

पटना नगर निगम द्वारा नगर क्षेत्र के विभिन्न प्रमंडलों में सामुदायिक भवन निर्माण, सड़क निर्माण, सड़क पुनर्स्थापन, नाला निर्माण सहित विभिन्न आधारभूत संरचना और नागरिक सुविधा संबंधी योजनाओं का काम शुरू किया गया है। इन योजनाओं के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, तकनीकी मानकों के अनुपालन और कार्यों की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के उद्देश्य से गठित जांच दल निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, नालों में इनलेट एवं आउटलेट की उपलब्धता, स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप कार्य निष्पादन तथा अन्य तकनीकी पहलुओं की जांच करेंगे।

निरीक्षण के साथ जियो-टैग्ड फोटोग्राफ देना जरूरीः इसके साथ ही प्रत्येक परियोजना की जियो-टैग्ड फोटोग्राफ सहित डिटेल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। जांच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता, त्रुटि, मानक से विचलन अथवा वित्तीय/तकनीकी विसंगति पाए जाने पर संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी एवं उत्तरदायी पदाधिकारी/अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी अनुशासनात्मक एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पटना में शराब-गैस की कालाबाजारी का भंडाफोड़, शास्त्रीनगर से पति-पत्नी गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान

पटनाः पटना के शास्त्रीनगर इलाके में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गैस सिलेंडर और शराब कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सोनू नामक व्यक्ति के मकान में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 56 डोमेस्टिक और कमर्शियल गैस सिलेंडर और विदेशी शराब बरामद की गई है। इसकी बाजार में अनुमानित कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है।

अवैध कारोबार में शामिल पति-पत्नी गिरफ्तारः पुलिस जांच में सामने आया कि इस अवैध कारोबार में पति और पत्नी दोनों इस धंधे में संलिप्त थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी पहचान सोनू और बबली के रूप में हुई है। मामला शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के रवि चौक नाला इलाके का है।

'युद्ध की खबर के बाद कमाई का लगा मौका': पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि, 'युद्ध संबंधी खबरों के बाद उन्हें लगा कि गैस सिलेंडर की मांग बढ़ेगी और इससे ज्यादा कमाई की जा सकती है। इसके बाद उन्होंने सिलेंडर जमा करना शुरू किया।' पूछताछ में यह भी सामने आया कि जरूरतमंदों को एक सिलेंडर 2500 से 3000 रुपए तक में बेचा जाता था। पुलिस के अनुसार, दोनों पिछले करीब दो वर्षों से अवैध शराब और गैस सिलेंडर के कारोबार में सक्रिय थे।

आपूर्ति विभाग के साथ हुई संयुक्त कार्रवाईः टाउन डीएसपी-1 डॉ. अन्नू कुमारी ने बताया कि, 'गुप्त सूचना मिलने के बाद सत्यापन के लिए आपूर्ति निरीक्षक के साथ पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान भारत गैस और इंडियन गैस के कुल 56 सिलेंडर बरामद किए गए। इसके अलावा बड़ी मात्रा में विदेशी शराब भी जब्त की गई।'

सप्लाई चेन की जांच जारीः पुलिस उनके दूसरी लिंकेज को भी खांगाल रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर सिलेंडर इन्हें कौन उपलब्ध करा रहा था। इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। मामले में आगे की जांच जारी है।

चीन, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान से मेडिकल पढ़कर आए बिहारी स्टूडेंट, एफएमजीई एग्जाम पास होने के बावजूद नहीं मिली इंटर्नशिप

लोकतंत्र की शान

पटनाः फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन (FMGE) पास आउट स्टूडेंट ने आज पटना की सड़कों पर उतर के प्रदर्शन किया। उन्होंने बिहार काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की। चीन, यूक्रेन, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, सऊदी अरब से पढ़ाई करके आए बिहारी स्टूडेंट की यह शिकायत है कि उन्हें अभी तक इंटर्नशिप अलॉट नहीं हुई है, जिस कारण से आगे पीजी एग्जाम में उन्हें काफी परेशानी होगी। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से भी दो बार मुलाकात की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है।

स्वास्थ्य मंत्री से दो बार की मुलाकात, नहीं मिला कोई जवाबः FMGE पास आउट स्टूडेंट डॉ श्वेता ने कहा कि, '17 जनवरी 2026 में हम सभी ने FMGE का एग्जाम दिया था और 28 जनवरी को रिजल्ट आया था, जिसमें हम सभी अच्छे नंबर के साथ उत्तीर्ण हुए थे। रिजल्ट आने के 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारा इंटर्नशिप या एलोकेशन लिस्ट अलॉट नहीं हुआ है। इसके लिए हम सचिवालय भी गए, लेकिन वहां हर कोई दूसरे आदमी पर मामले को डाल देता है।'

चीन, यूक्रेन, कज़ाख़िस्तान, किर्गिस्तान से मेडिकल पढ़ाई कीः FMGE पास आउट स्टूडेंट डॉ मोहम्मद एजाज ने कहा कि, 'हम लोग चीन, यूक्रेन, कज़ाख़िस्तान, किर्गिस्तान, रसिया से एमबीबीएस करके आए हैं। हम लोग ने 2025 का FMGE एग्जाम दिया है, जो भारत सरकार यह चेक करने के लिए लेती है कि जो हम विदेश से एमबीबीएस पढ़ कर आए हैं, तो हम इंडिया में डॉक्टर बनने लायक है या नहीं। हम सभी ने वह एग्जाम दिया और पास भी किया है। यानी भारत में डॉक्टर बनने का भारत सरकार का जो क्राइटेरिया है हम उसे पूरा करते हैं।'

इस एग्जाम में पूरे बिहार से 428 स्टूडेंट हुए पासः FMGE पास आउट स्टूडेंट डॉ रितेश कुमार ने कहा कि, 'इस एग्जाम में पूरे बिहार से 428 स्टूडेंट ने पास किया था। हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द एलोकेशन लिस्ट जारी कर दिया जाए, ताकि हमें जो कॉलेज मिलेगा, वहां 1 साल का इंटर्नशिप करेंगे।'

6 महीने से हमें इंटर्नशिप अलॉट नहीं हुआ- डॉ अली अहमदः FMGE पास आउट स्टूडेंट डॉ अली अहमद ने कहा कि, '6 महीने से हमें इंटर्नशिप अलॉट नहीं हुआ है। जब विदेश से हम लोग मेडिकल शिक्षा प्राप्त करके आते हैं तो भारत में हमें इंटर्नशिप के तहत 1 साल का सेवा देना होता है।

16 से 18 जून तक सभी प्रखंडों में सहयोग सह जनकल्याण शिविर का आयोजन

लोकतंत्र की शानः मो. जियाउद्दीन, जिला संवाददाता

सहरसाः प्राप्त सूचना के अनुसार जिले के सभी प्रखंडों में दिनांक 16, 17 एवं 18 जून 2026 को पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक सहयोग सह जनकल्याण शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्तियों तक सुनिश्चित रूप से पहुंचाना है। शिविर के दौरान विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन, निबंधन, सत्यापन, ई-केवाईसी सहित लंबित मामलों का निष्पादन किया जाएगा तथा पात्र लाभार्थियों के बीच देय लाभों का वितरण भी सुनिश्चित किया जाएगा।

शिविर में शामिल प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं:

पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना

इस योजना के अंतर्गत घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।

मुख्य लाभः

- प्रति माह लगभग 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली
- रूफटॉप सोलर पर सरकारी सब्सिडी
- अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचने की सुविधा (नेट मीटरिंग)

पात्रताः

- भारतीय नागरिक
- स्वयं के नाम का आवासीय मकान
- वैध बिजली कनेक्शन
- उपयुक्त छत की उपलब्धता

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना- इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पेंशन प्रदान की जाती है। पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

पीएम स्वनिधि योजना- यह योजना रेहड़ी-पटरी एवं सड़क विक्रेताओं को बिना गारंटी कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है।

योजना की अवधि 31 मार्च 2030 तक विस्तारित

आवेदन PM SVANidhi पोर्टल, बैंक, नगर निकाय या CSC के माध्यम से

विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार एवं आजीविका सुदृढ़ करने हेतु संचालित है, जिसके तहत परिवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं।

लखपति दीदी (SHG लिंकेज)

इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख या उससे अधिक करना है।

मुख्य विशेषताएंः

- बैंक लिंकेज के माध्यम से ऋण सुविधा
- कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प आदि गतिविधियों को बढ़ावा
- कौशल एवं उद्यमिता प्रशिक्षण
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)
- किसानों को खेती एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए सस्ता एवं सुलभ ऋण उपलब्ध कराने की योजना।

मुख्य लाभः कम ब्याज दर पर ऋण, फसल, पशुपालन एवं मत्स्य पालन हेतु सहायता

आवश्यक दस्तावेजः आधार कार्ड, पहचान एवं पता प्रमाण, भूमि से संबंधित दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता विवरण

प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे शिविर में पहुंचकर योजनाओं का लाभ उठाएं तथा अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने में सहयोग करें।

सबका सम्मान, जीवन आसानः जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने 32 जनशिकायतों की सुनवाई कर दिए त्वरित निष्पादन के निर्देश

लोकतंत्र की शान

सबका सम्मान,जीवन आसान अंतर्गत आज दिनांकः15.06.26 को जिलाधिकारी श्री दीपेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित आम जनता से संवाद के दौरान कुल बत्तीस आवेदनों के संदर्भ में सुनवाई की गई।सुनवाई क्रम में श्रीमती ऊषा देवी,सहूरिया पश्चिमी ने भूमि विवाद सम्बन्धित आवेदन दिया,जिसके निष्पादन हेतु अंचलाधिकारी कहरा को निर्देशित किया गया है।श्री दिनेश यादव, बलुआहा, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा समर्पित आवेदन के निष्पादन हेतु अंचलाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर को निर्देशित किया गया है।श्री विमलकांत झा,कहरा निवासी/राधा देवी,सहरसा निवासी द्वारा दिए गए भूमि विवाद विषयक आवेदनों के निष्पादन हेतु संबंधित अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उक्त अवसर पर उप विकास आयुक्त श्री गौरव कुमार,अपर समाहर्ता(वि०जांच) श्री गणेश कुमार सहित अन्य संबंधित उपस्थित थे।

बाढ़ में 48 साल बाद ससुराल लौटी पत्नी, पति की आंखों में छलक पड़े आंसू

लोकतंत्र की शानः पटना

पटना जिले के बरियारपुर गांव में एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरे इलाके को भावुक कर दिया। करीब 48 साल पहले ससुराल छोड़कर चली गई महिला अब अपने पति के पास लौट आई। इतने लंबे इंतजार के बाद पत्नी को सामने देखकर पति की आंखें भर आईं और परिवार में खुशी का माहौल बन गया।

ललन मिश्रा ने बताया कि, उनकी शादी मार्च 1977 में निर्मला देवी से हुई थी। शादी के करीब छह महीने बाद निर्मला देवी ससुराल छोड़कर अपने मायके दरभंगा चली गई थीं और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटीं। ललन मिश्रा ने अपनी पत्नी को आसपास के गांवों में ढूंढा और इस दौरान उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी। निर्मला देवी ने बताया कि, 'ससुराल के कुछ लोगों ने उन्हें भड़काकर घर छोड़ने पर मजबूर किया था। घर छोड़ने के बाद वह अपने मायके में रहीं। बाद में उनके पिता ने उनकी नौकरी नागपुर के एक सरकारी स्कूल में लगवा दी। तब से वह अपने दो बच्चों के साथ नागपुर में रह रही हैं। उनका एक बेटा पुणे में इंजीनियर है, जबकि दूसरा अभी पढ़ाई कर रहा है। निर्मला देवी बरियारपुर आने से पहले बख्तियारपुर थाना पहुंचीं और अपने पति के बारे में जानकारी ली।

प्रशांत किशोर बोले- 10 हजार रुपए में खरीदे गए वोट

लोकतंत्र की शानः पटना

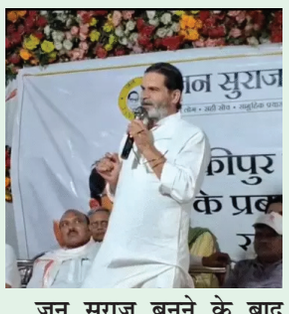

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में जन सभा के दौरान बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बिहार में पदयात्रा शुरू की थी, तब अधिकांश लोगों को उनके प्रयास पर भरोसा नहीं था।लोग उन्हें सलाह देते थे कि वे बेकार में समय बर्बाद कर रहे हैं क्योंकि बिहार में कुछ नहीं बदल सकता। यहां तक कि उनके परिवार और करीबी लोगों ने भी सवाल उठाया कि जब जीवन अच्छी तरह चल रहा है तो बिहार की राजनीति में संघर्ष करने की क्या जरूरत है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इसके बावजूद उन्होंने और उनके साथियों ने लगातार दो से ढाई वर्षों तक मेहनत की और गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद स्थापित किया।

जन सुराज बनने के बाद बदलाव की उम्मीद दिखाई देने लगीः प्रशांत किशोर ने कहा कि लंबे प्रयासों के बाद जब जन सुराज एक राजनीतिक दल के रूप में सामने आया और उसकी गतिविधियों की चर्चा सोशल मीडिया तथा आम लोगों के बीच होने लगी, तब पहली बार लोगों को यह महसूस हुआ कि बिहार में राजनीतिक बदलाव संभव है। जन सुराज के बढ़ते जनाधार और लोगों की बढ़ती भागीदारी ने एक नई उम्मीद पैदा की थी कि इस बार राज्य की राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है।

बदलाव की हवा देखकर सत्ता में बैठे दल सक्रिय हो गएः प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि जैसे ही यह माहौल बना कि बिहार में बदलाव की संभावना बढ़ रही है, वैसे ही पिछले 30-35 वर्षों से सत्ता में प्रभाव रखने वाले राजनीतिक दल और नेता पूरी ताकत के साथ सक्रिय हो गए। जब उन्हें लगा कि जनता का रुझान बदल सकता है और जन सुराज को समर्थन मिल सकता है, तब चुनावी मुकाबले को प्रभावित करने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए गए।

'10 हजार रुपये देकर वोट खरीदे गए': प्रशांत किशोर ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटे गए। उनका दावा था कि कई जगहों पर लोगों को 10-10 हजार रुपये तक दिए गए और वोट खरीदने की कोशिश की गई। बिहार जैसे गरीब राज्य में यह कोई छोटी बात नहीं है। उनके अनुसार, एक विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ रुपये तक खर्च किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के टैक्स और सरकारी संसाधनों से जुड़े धन का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया गया।

लोगों ने सोचा कि पैसा देने वालों को ही वोट दे देंः प्रशांत किशोर ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके के कई लोगों ने यह सोचकर उन्हीं दलों का समर्थन किया जिन्होंने उन्हें चुनाव के दौरान आर्थिक लाभ पहुंचाया। गरीबी और आर्थिक जरूरतों के कारण कई मतदाता तत्काल लाभ के प्रभाव में आ गए और बदलाव की राजनीति को समर्थन नहीं दे सके।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लमतरा बस हादसे पर जताया शोक, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये सहायता के दिए निर्देश

लोकतंत्र कि शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश , कटनी। जिले के कुठला थाना क्षेत्र अंतर्गत लमतरा ब्रिज के समीप हुए भीषण सड़क हादसे में बस यात्रियों की मृत्यु पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री इस दुर्घटना को अत्यंत पीड़ादायक बताते हुए दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना

की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने शोक संदेश में कहा कि लमतरा ब्रिज के पास हुई सड़क दुर्घटना में बस यात्रियों के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा घायल यात्रियों को शीघ्र स्वस्थ करें। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में प्रदेश सरकार शोकाकुल परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि दुर्घटना में मृत प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए तथा घायलों के समुचित उपचार में किसी प्रकार की कमी न रहने दी जाए।

अब सिर्फ स्टेशन नहीं,नागौर की नई पहचान बना आधुनिक रेलवे स्टेशन

अमृत भारत योजना के तहत 96 फीसदी काम पूरा
यात्रियों को मिलने लगी आधुनिक सुविधाएं

लोकतंत्र की शान , नागौर/मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। बदलाव जब दिखने लगे तो इंतजार भी सार्थक लगने लगता है। करीब ढाई साल तक चले पुनर्विकास कार्य के बाद अब नागौर रेलवे स्टेशन नए स्वरूप में उभर रहा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन का लगभग 96 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलना शुरू हो गया है। आने वाले समय में यह स्टेशन केवल रेल यात्रा का केंद्र नहीं बल्कि नागौर की नई पहचान के रूप में भी देखा जाएगा। स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों को सबसे पहले नया मुख्य प्रवेश द्वार स्वागत करता नजर आता है। पहले जहां निर्माण कार्य के कारण अस्थाई व्यवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता था,वहीं अब चौड़ा और सुव्यवस्थित प्रवेश मार्ग यात्रा को अधिक आसान और आरामदायक बना रहा है। रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों के लिए यह बदलाव सुविधा और समय दोनों की बचत लेकर आया है।

अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार की बड़ी कार्यवाही

राजन रिसोर्ट परसिली के अतिक्रमण को कराया मुक्त

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान सीधी। जिले के तहसीलदार मझौली द्वारा अतिक्रमण को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है जो क्षेत्र में चर्चा के विषय बना है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राजन रिसोर्ट परसिली में शासकीय भूमि पर रिसोर्ट के मलिक रामराज मिश्रा के द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर उसे बाउंड्री वॉल बनाकर अपने कब्जे में ले लिया गया था। अतिक्रमण को लेकर हल्का पटवारी के द्वारा तहसील कार्यालय में प्रतिवेदन दिया गया था जिसमें तहसीलदार के द्वारा विधिवत सुनवाई के उपरांत बेदखली का आदेश पारित किया जाकर 12जून को मौके पर किए गए अतिक्रमण को भी जाकर हटाया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक राजस्व ग्राम परसिली में ही कई उद्योगपतियों के द्वारा इसी तरह रिसोर्ट या फार्म हाउस बनाए गए हैं जिनके द्वारा बड़ी मात्रा में शासकीय जमीन में अतिक्रमण कर उसे अपने कब्जे में लिया गया है अगर इसी तरह कार्रवाई की जाएगी तो काफी शासकीय जमीन कब्जे से मुक्त भी हो सकती है और प्रशासनिक कसावट भी आ सकती है।

इनका कहना है। हल्का पटवारी के द्वारा प्रतिवेदन दिया गया था उसी के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है।शासकीय जमीन में बाउंड्री वॉल का निर्माण किया गया था जिसे हटाया गया है। दिलीप सिंह तहसीलदार मझौली।

खरीफ सीजन से पहले किसानों को मिला आधुनिक खेती का ज्ञान

टाकंला में आत्मा योजना की गोष्ठी आयोजित

लोकतंत्र की शान , नागौर/मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। खरीफ सीजन की तैयारियों के मद्देनजर आत्मा योजना के तहत सोमवार को खींवसर पंचायत समिति के ग्राम टाकंला में एक दिवसीय किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में अनुसूचित जाति वर्ग के 125 किसानों ने भाग लेकर आधुनिक कृषि तकनीकों, जैविक खेती तथा मिट्टी परीक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कीं।<कार्यक्रम में कृषि विभाग नागौर के उप निदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक आत्मा नागौर डॉ. हेमराज मीना ने किसानों को आत्मा योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं नवीन कृषि पद्धतियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक तरीके अपनाकर खेती में उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के उपाय भी बताए।

डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग 'त्रिवेणी' का समापन समारोह

लोकतंत्र की शान ,लखनऊ। लखनऊ स्थित एक होटल में तीन दिवसीय डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग 'त्रिवेणी' में सोमवार को समापन समारोह में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के सुशासन, संस्कृति और समृद्धि पर चर्चा हुई। चर्चा का मुख्य केंद दो सत्र में समद्धि (महिला एवं यवा) और सांस्कृतिक पुर्नजागरण रहा। चर्चा के दौरान अतिथियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश की भविष्य की समृद्धि काफी हद तक उसकी महिलाओं और युवाओं की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने की काबिलियत पर निर्भर करेगी। पहले सत्र में प्रदेश के समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि डेमोक्रेसी में हम अपने लीडर और जनसेवकों को चुन सकते हैं। इसके साथ कानून और समानता समाज में जरूरी है। आने वाला समय में डिजिटल क्रांति होगी, जिसके लिए हमें हर चीज सीखनी होगी। उन्होंने कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स ने नई राह खोली है। सीएम योगी बार-बार याद दिलाते है कि किसी भी नई पॉलिसी पर जनता से फीडबैक लो, इसलिए हम सोशल मीडिया की भी मदद लेते हैं।

अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन करते 407 टीपर वाहन जप्त

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अमन मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना बहरी पुलिस द्वारा अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक 407 टीपर वाहन जप्त किया गया है। दिनांक 15 जून 2026 की रात्रि गश्त के दौरान थाना बहरी पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम भरुही स्थित गोपद नदी घाट से अवैध रूप से रेत का उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा है। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की गई। गोपद नदी घाट के समीप एक 407 अशोक लीलैण्ड टीपर वाहन क्रमांक यूपी 64टी 6055 आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वाहन चालक ने नदी घाट से लाई गई रेत को मौके पर ही डंप कर दिया तथा भागने का प्रयास किया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम रितेश रजक (21 वर्ष), निवासी ग्राम भरुही, थाना बहरी बताया। वाहन में परिवहन की जा रही रेत के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे जाने पर वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जांच में वाहन स्वामी आशीषधर द्विवेदी निवासी ग्राम भरुही, थाना बहरी होना पाया गया। प्रथम दृष्टया अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन का अपराध पाए जाने पर पुलिस द्वारा वाहन को जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध धारा 303(2), 317(5) बीएनएस एवं धारा 4/21 खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

किसानों को खाद वितरण में न हो कोई परेशानी : कलेक्टर विकास मिश्रा

(ऋचा पाण्डेय, ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। खरीफ सीजन को देखते हुए कलेक्टर विकास मिश्रा ने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के खाद वितरण एवं भंडारण केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को खाद प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा या अनावश्यक इंतजार का सामना न करना पड़े। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने खाद वितरण में टोकन प्रणाली लागू करने, किसानों के लिए छाया, पेयजल एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उर्वरक निर्धारित शासकीय दरों पर ही वितरित किया जाए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने महिला एवं पुरुष किसानों के लिए अलग-अलग कतारों की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अधिकारियों को नियमित रूप से वितरण केंद्रों की निगरानी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि खरीफ सीजन में किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध हो और उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

63 लीटर अवैध देशी शराब सहित कार चालक गिरफ्तार

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के कुशल निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती कमला जोशी एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अमन मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना बहरी पुलिस को अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार दिनांक 14/15 जून 2026 की रात्रि में थाना बहरी पुलिस की गश्ती टीम द्वारा ग्राम मयापुर क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक आल्टो कार में अवैध शराब लोड कर अमिलिया की ओर से सीधी ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सोन नदी पुल के पास घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन आल्टो कार क्रमांक एमपी 53 जेडए 6057 को रोककर जांच की। वाहन चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मिथुन सिंह बघेल (23 वर्ष), निवासी ग्राम लकोड़ा, थाना कमर्जी, जिला सीधी बताया। वाहन की तलाशी लेने पर डिक्की में रखी 07 पेटियों में कुल 350 पाव (63 लीटर) अवैध देशी प्लेन शराब बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 28,000 है। आरोपी द्वारा शराब परिवहन संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर पुलिस ने अवैध शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त वाहन को जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक दर्ज कर धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

विजयराघवगढ़ विधानसभा में सांसद वीडी शर्मा ने गिनाईं मोदी सरकार की 12 साल की उपलब्धियां

» प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजनीति सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा का संकल्प है: संजय पाठक

लोकतंत्र कि शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर सांसद विष्णु दत्त शर्मा, विधायक संजय पाठक ने विजयराघवगढ़ के सभी सात मंडलों में अलग अलग स्थानों पर आयोजित जनकल्याण शिविर, चौपाल बैठक, लाभार्थी संपर्क जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच पहुंचकर संवाद किया । जनकल्याण शिविर में हितग्राहियों को उनके हितलाभ का वितरण भी गया। इस दौरान जनकल्याण शिविर का शुभारंभ सांसद विष्णु दत्त शर्मा, सजंय पाठक, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सोनी टंडन नगर परिषद अध्यक्ष पलक गौवर, संतोष केवट के द्वारा दीप प्रज्वलन कर हुआ । जनता से संवाद करते हुए सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि सेवा व सुशासन का 12 वर्ष पूर्ण करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जनकल्याण, विकास और राष्ट्र निर्माण को समर्पित रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना किसी भेदभाव के समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। इसमें पक्के घर, स्वच्छ पेयजल और मुक्त इलाज आयुष्मान भारत जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल है। जनकल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जो भी लोग अब तक किन्हीं कारणों से योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं वह तीन दिनों तक चलने वाले शिविर व मेले में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें।

लमतरा फाटक के पास भीषण सड़क हादसा: बस और ओवरलोड हाइवा की टक्कर में 3 की मौत, 29 यात्री घायल

» कलेक्टर आशीष तिवारी और एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने अस्पताल पहुंचकर संभाली व्यवस्थाएं
» सांसद वीडी शर्मा ने जाना घायलों का हाल

लोकतंत्र कि शान हसन रशीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी: कुठला थाना क्षेत्र के लमतरा फाटक के समीप रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में यात्री बस और ओवरलोड हाइवा के बीच आमने-सामने की भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना भयावह था कि बस में सवार एक महिला सहित तीन लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जबकि लगभग 29 यात्री गंभीर एवं सामान्य रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद घटनास्थल से एंबुलेंस के माध्यम से घायलों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यात्री बस क्रमांक एमपी-19-पी-0347 और ओवरलोड हाइवा के बीच लमतरा फाटक के पास जोरदार भिड़ंत हुई। टक्कर के प्रभाव से बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री उसमें फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर आशीष तिवारी और पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा जिला चिकित्सालय पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने आपातकालीन वार्ड का निरीक्षण कर घायलों से मुलाकात की तथा चिकित्सकों को घायलों को बेहतर उपचार मुहैया कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री तिवारी ने गंभीर घायलों के लिए विशेष चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी मरीजों को सर्वोत्तम उपचार उपलब्ध कराया जाए।

नागौर आईटीआई में सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों एवं साइबर जागरूकता पर एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित

लोकतंत्र की शान

नागौर/मेड़ता रोड , एजाज़ अहमद उस्मानी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नागौर आशा राम चौधरी (आरपीएस) के निर्देशन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) नागौर में सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों तथा साइबर जागरूकता विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षणार्थियों को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, सुरक्षित यातायात व्यवहार और बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता यातायात उप अधीक्षक पुलिस श्री उम्मेद सिंह ने सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि वाहन चलाते समय निर्धारित गति सीमा का पालन करना प्रत्येक चालक की जिम्मेदारी है। उन्होंने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने, नशे की अवस्था में वाहन नहीं चलाने, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने, लेन अनुशासन बनाए रखने, यातायात संकेतों का पालन करने तथा पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया।

टमसार में सड़क किनारे खोदी गई नाली को लेकर विवाद

» व्यापारियों ने वन विभाग पर लगाए गंभीर आरोप

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के जनपद पंचायत कुसमी अंतर्गत ग्राम टमसार में कुसमी-महखोर मार्ग पर सड़क किनारे खोदी गई नाली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों एवं ग्रामीणों ने वन विभाग पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा है कि चौराहे के समीप नाली निर्माण से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत चौराहे क्षेत्र में व्यापारियों और गुमटी संचालकों को परेशान करने की नीयत से सड़क किनारे नाली खोदी गई है। उनका कहना है कि नाली बनने के बाद आवागमन प्रभावित हुआ है तथा दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीणों ने बताया कि वन विभाग के कथित तानाशाही रवैये के कारण क्षेत्र में अक्सर दुर्घटना जैसी स्थितियां निर्मित हो रही हैं। बरसात के मौसम में यह नाली और भी अधिक खतरनाक साबित हो सकती है, जिससे राहगीरों एवं वाहन चालकों की जान को खतरा उत्पन्न होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय व्यापारियों एवं गुमटी संचालकों द्वारा इस संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच मकरंद सिंह के समक्ष भी शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। वहीं मामले की जानकारी मिलने पर तहसीलदार कुसमी नारायण सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थल का निरीक्षण कर नाप-जोख कराई। बताया जा रहा है कि तहसीलदार ने ग्रामीणों को जानकारी दी कि संबंधित भूमि के रिकॉर्ड एवं सीमांकन के अनुसार उक्त क्षेत्र में अवैध नाली खोदी गई जो पचासा में है। हालांकि ग्रामीणों और व्यापारियों का कहना है कि यदि नाली आवश्यक है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था, ढक्कन एवं चेतावनी संकेत लगाए जाएं, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। अब बड़ा सवाल यह है कि यदि बरसात के दौरान इस नाली के कारण कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर जनहित में उचित निर्णय लेने की मांग की है।

भवरसेन घाट में पिकनिक मनाने आए चार युवा डूबे

» सोन नदी के गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा
» रेस्क्यू में एक युवती का शव बरामद, अन्य की सर्चिंग

(ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख) लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के भंवरसेन घाट पर पिकनिक मनाने आए चार युवक-युवतियां सोन नदी में नहाते समय डूब गए। रेस्क्यू अभियान में एक युवती का शव बरामद हुआ है, जबकि तीन अन्य की तलाश जारी है। घटना से परिजनों में मातम पसरा है। जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र स्थित सोन नदी के भंवरसेन घाट पर सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया। मैहर जिले से परिवार और रिश्तेदारों के साथ पिकनिक मनाने आए चार युवक-युवतियां नदी में नहाते समय गहरे पानी और भंवर की चपेट में आकर डूब गए। देखते ही देखते चारों नदी में समा गए, जिससे घाट पर अफरा-तफरी मच गई और परिजनों में चीख-पुकार गूंज उठी। मिली जानकारी के अनुसार घटना सोमवार दोपहर करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विकास आनंद, तहसीलदार रामपुर नैकिन आशीष मिश्रा, रामपुर नैकिन थाना पुलिस और खड्डी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। प्रशासन ने तत्काल रेस्क्यू टीम को बुलाकर खोजबीन शुरू कराई। तलाशी अभियान के दौरान एक युवती का शव घटनास्थल से करीब आधा किलोमीटर दूर नदी में तैरता हुआ मिला। शव की पहचान ज्योति सेन पिता रामाधार सेन 24 निवासी बूढ़ा बाउर, थाना रामनगर जिला मैहर के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा परिजनों को सूचना दे दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस और बचाव दल लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। आशंका है कि सभी लोग नदी के गहरे भंवर में फंस गए थे, जिसके कारण वे बाहर नहीं निकल सके।

संक्षिप्त समाचार

नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस के बड़े बेटे को चार साल की जेल

ओस्लो। नॉर्वे में शाही परिवार की क्राउन प्रिंसेस मेटे-मैरिट के बड़े बेटे मारियस बोर्ग होइबी को यौन अपराधों से जुड़े एक मामले में दोषी पाए जाने के बाद सोमवार को चार साल जेल की सजा सुनाई गई। अदालत ने होबी के खिलाफ लगाए गए चार आरोपों में से दो में उन्हें दोषी ठहराया, जबकि दो अन्य आरोपों से बरी कर दिया। अदालत के फैसले के अनुसार ये मामले उन महिलाओं से जुड़े थे जो कथित रूप से सो रही थीं या किसी कारणवश विरोध करने की स्थिति में नहीं थीं। आरोप है कि ये अपराध 2018 और 2024 के बीच हुए थे। इसके अलावा, होइबी को कई अन्य आरोपों का भी सामना करना पड़ा, जिनमें हमला, नशीली दवाओं से जुड़े अपराध और अदालत द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन शामिल था। हालांकि, होइबी ने गंभीर आरोपों से इनकार किया, लेकिन उन्होंने कुछ कम गंभीर अपराधों, जैसे नशीली दवाओं से संबंधित उल्लंघनों और कानूनी आदेशों के उल्लंघन को स्वीकार किया था। यह मामला नॉर्वे में व्यापक चर्चा का विषय बना रहा क्योंकि होइबी, मेटे-मैरिटके सबसे बड़े बेटे हैं। होबी का जन्म क्राउन प्रिंसेस की प्रिंस हाकोनसे शादी से पहले के एक रिश्ते से हुआ था। हालांकि होइबी के पास कोई शाही उपाधि नहीं है और वे आधिकारिक शाही दायित्व नहीं निभाते हैं, फिर भी शाही परिवार से उनके संबंध के कारण मुकदमे पर देशभर की नजर बनी रही। यह मुकदमा कई सप्ताह तक चला, जिसमें अदालत ने कई शिकायतकर्ताओं की गवाही सुनी और प्रस्तुत साक्ष्यों की विस्तृत जांच की। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए होइबी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों पर विचार करेंगे

मॉस्को। यूरोपीय संघ (ईयू) के विदेश मंत्री सोमवार को लक्ज़मबर्ग में होने वाली बैठक में रूस के लोगों, कंपनियों और संगठनों के खिलाफ़ 'व्यक्तिगत प्रतिबंधों की सूची को बढ़ाने पर विचार करेंगे। ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास ने बैठक से पहले कहा, "हम आज और भी नाम और प्रतिबंध लेकर आ रहे हैं; हम रूस के सैन्य-औद्योगिक ढांचे के साथ-साथ 'गुप्त रूप से काम करने वाले जहाजों के बेड़े पर भी काम कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि यूरोपीय आयोग उन रूसियों की सूची तैयार करने की योजना बना रहा है जिन्होंने यूक्रेन में 'विशेष सैन्य अभियान में हिस्सा लिया था, ताकि उन्हें शेंगेन ज़ोन के देशों में प्रवेश करने से रोका जा सके। कल्लास ने कहा कि वह वीज़ा नीति की विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा करना संभव है। ईयू आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने पिछले हफ़्ते रूस के खिलाफ़ प्रतिबंधों के 21वें पैकेज के लिए प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि ईयू उन लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव कर रहा है जिन्होंने 2022 से रूसी सशस्त्र बलों में सेवा की है। रूस ने बार-बार कहा है कि वह उन प्रतिबंधों के दबाव का सामना कर लेगा जो पश्चिम ने कई साल पहले उस पर डालने शुरू किए थे और जिन्हें लगातार बढ़ाया जा रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन ने पहले कहा था कि रूस को रोकने और कमज़ोर करने की नीति पश्चिम की एक दीर्घकालिक रणनीति है और इन प्रतिबंधों ने पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है।

ओडिशा में एक परिवार के सामाजिक बहिष्कार मामले का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में घटी एक अमानवीय घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। जिले के महुलदिहा गांव में एक परिवार को पिछले 12 सालों से कथित सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा था। इस बीच परिवार की एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु होने पर ग्रामीणों ने उनके अंतिम संस्कार में सहयोग देने से भी साफ इनकार कर दिया। आयोग ने सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार विवाद करीब 12 साल पहले शुरू हुआ था। पीड़ित परिवार की बेटी कुछ समय के लिए दूसरी जाति के एक व्यक्ति के साथ घर से बाहर चली गई थी। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने परिवार पर भारी जुर्माना लगा दिया। परिवार बेहद गरीब था और जुर्माने की रकम चुकाने में असमर्थ था इसलिए ग्रामीणों ने पूरे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया। खबर के मुताबिक, 12 वर्षों तक इस सामाजिक दंश को झेलने के बाद हाल ही में परिवार की बुजुर्ग महिला का निधन हो गया। ग्रामीणों ने अंतिम संस्कार में बेटी या परिवार की मदद करने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों के इस अमानवीय रुख के बाद स्थानीय प्रशासन ने मामले में हस्तक्षेप किया। प्रशासन और कुछ स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के सहयोग व सक्रिय प्रयासों से बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार संपन्न कराया जा सका।

कोलकाता में सीएम शुभेंदु के मंच पर दिखे फिरहाद व ममता बनर्जी की भाभी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार कोलकाता नगर निगम (केएमसी) मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मंच और कार्यक्रम स्थल पर तृणमूल कांग्रेस से जुड़े कई प्रमुख नेता, पार्षद और पूर्व जनप्रतिनिधि मौजूद दिखाई दिए। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भाभी तथा वार्ड संख्या 73 की पार्षद काजरी बनर्जी भी उपस्थित रहीं। उनके अलावा केएमसी के पूर्व मेयर और हाल ही में पद से इस्तीफा देने वाले फिरहाद हाकिम भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर पार्षद अनन्या बनर्जी, जुई विश्वास, पूर्व विधायक देबाशीष कुमार सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। कार्यक्रम में राज्य मंत्री शशि पांजा की बेटी और मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के पुत्र की उपस्थिति भी चर्चा का विषय रहा। केएमसी में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने "स्वच्छता से स्वागत" अभियान का शुभारंभ किया। मंच पर उनके साथ दक्षिण कोलकाता की सांसद माला राय, संदीपन साहा और जावेद खान भी मौजूद रहे। राजनीतिक रूप से इस कार्यक्रम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी की नगर निगम में यह पहली आधिकारिक उपस्थिति थी। कार्यक्रम में विभिन्न दलों और राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता, नागरिक सेवाओं और शहरी विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई तथा नगर निगम क्षेत्र में चलाए जाने वाले स्वच्छता अभियानों को लेकर भी संदेश दिया गया।

राजधानी में मंगलवार को फिर बरसेंगे बदरा, तेज हवाओं का सिलसिला रहेगा जारी

नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के पूर्वानुसार दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। इससे यहां का मौसम सुहावना हो गया है। वहीं दक्षिण-पश्चिम मानसून बिहार, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक आगे बढ़ चुका है। आईएमडी के अनुसार राजधानी में मंगलवार को दोपहर और शाम के दौरान के समय तेज हवाओं और गरज के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। इस दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 38-40 डिग्री सेल्सियस और 26-28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। 17 जून को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। राजधानी का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 39-41 डिग्री सेल्सियस और 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हवाओं की गति सामान्य रहेगी। 18 जून को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 40-42 डिग्री सेल्सियस और 28-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मानसून आज आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों में और आगे बढ़ गया है। अगले 6-7 दिनों के दौरान उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों के दौरान तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में लू चलने की बहुत संभावना है।

तेज रफ्तार प्राइवेट बस खेत में पलटी, तीन यात्रियों की मौत

एजेंसी, फतेहाबाद

हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सोमवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां टोहाना आ रही एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गई। इस दर्दनाक दुर्घटना में एक महिला समेत 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने टोहाना-फतेहाबाद रोड पर चक्का जाम कर दिया है, जिससे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।

12 घायल

पुलिस और चश्मदीदों के मुताबिक, हादसे का शिकार हुई प्राइवेट बस में क्षमता से अधिक करीब 50 से 55 सवारियां मौजूद थीं। बस में सवार यात्री राममेहर निवासी गांव चंदड़ ने बताया कि ड्राइवर शुरुआत से ही बस को बेहद तेज गति और लापरवाही से चला रहा था। जैसे ही बस गांव भोडी के पास एक कट पर पहुंची, ड्राइवर ने तेज रफ्तार में ही बस को अचानक मोड़ दिया। रफ्तार अधिक होने के कारण ड्राइवर वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और बस पलटते हुए सीधे खेत में जा गिरी। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई। हादसे की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर तुरंत मदद के लिए दौड़े। उन्होंने मुस्तैदी दिखाते हुए बस के शीशे तोड़े और भीतर फंसे घायल व सहमे हुए यात्रियों को बाहर निकाला।

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी बीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। फिलहाल मृतकों की पहचान की कोशिश की जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने खुद खड़े रहकर घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था की और प्रशासनिक अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने तथा घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के सख्त निर्देश दिए। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों का चक्का जामइस दर्दनाक हादसे के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना के तुरंत बाद आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए, जिससे नाराज होकर गुस्साए ग्रामीणों ने गांव भोड़ी में टोहाना-फतेहाबाद रोड पर धरना शुरू कर दिया और चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ड्राइवरों की इस तरह की लापरवाही आए दिन मासूमों की जान ले रही है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक फरार ड्राइवर और कंडक्टर को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे सडक़ से नहीं हटेंगे और उनका आंदोलन जारी रहेगा। कुछ लोगों ने चालक के नशे में होने की भी बात कही है।

उच्च स्तरीय शिक्षा योजना के तहत 4,742 वंचित छात्र लाभ पा सके

एजेंसी, नई दिल्ली

केन्द्र सरकार की उच्च स्तरीय शिक्षा योजना के तहत पेशेवर, शोधकर्ता और उद्यमी देश के विकास कार्यों को गति दे रहे हैं। यह योजना अनुसूचित जाति (एससी) के लिए है। अब तक 4,742 वंचित छात्र इस योजना का लाभ पा चुके हैं।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार सरकार का लक्ष्य यह है कि एससी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और सशक्त बनें। उन छात्रों के भी योगदान से राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल और आत्मनिर्भर बनेगा। इसमें नवप्रवर्तक और नेता भी शामिल हैं। इस योजना का लाभ उन्हीं छात्रों को मिल सकता है जिनके परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपये है। इन समुदाय के मेधावी छात्रों को उच्च संस्थानों में निशुल्क प्रवेश दिया जाता है। इन संस्थानों में छात्रों को अनुसंधान और नवाचार करने का अवसर प्राप्त होता है। इनके योगदान, लगन और मेहनत से राष्ट्र वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनता है।

फिलहाल, इस योजना के तहत छात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी), भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (एनएलयू), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी), भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) जैसे प्रमुख प्रबंधन संस्थानों और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों सहित प्रमुख संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

मंत्रालय के मुताबिक, यह योजना केन्द्र सरकार की शैक्षिक सशक्तिकरण, समावेशन और समान अवसर के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि इस योजना को 2007-08 में शुरू किया गया था। अब तक 4,742 छात्र इस योजना का लाभ पा चुके हैं। छात्रों पर खर्च होने वाला वार्षिक व्यय 2.17 करोड़ रुपये से बढ़कर 117.19 करोड़ हो गया है।

भारतीय रेलवे ने उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपये के कवच प्रोजेक्ट को मंजूरी दी

एजेंसी, नई दिल्ली

भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के शेष ब्रॉड गेज मार्गों पर 'कवच' प्रणाली स्थापित करने की 201 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना 811 रूट किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगी। रेल मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि इस कार्य को भारतीय रेलवे के शेष मार्गों पर एलटीई आधारित संचार नेटवर्क के साथ 'कवच' प्रणाली उपलब्ध कराने के व्यापक कार्यक्रम के तहत स्वीकृति दी गई है।

परियोजना के तहत अंबाला मंडल के कई महत्वपूर्ण रेलखंडों पर कवच प्रणाली स्थापित की जाएगी। इनमें अंबाला छावनी-लुधियाना, कालका-चंडीगढ़-न्यू मोरिंडा-साहनेवाल, सरहिंद-दौलतपुर चौक, राजपुरा-बठिंडा-श्रीगंगानगर तथा लुधियाना-धूरी-जाखल रेलखंड शामिल हैं। ये रेलमार्ग हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाले प्रमुख कॉरिडोर हैं, जहां यात्री और माल यातायात का भारी दबाव रहता है। क्षेत्र में लोगों और वस्तुओं के आवागमन में इन मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उल्लेखनीय है कि 'कवच' भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली सिग्नल पासिंग एट डेंजर (एसपीएडी) जैसी घटनाओं को रोकने, आवश्यकता पड़ने पर स्वतः ब्रेक लगाने, संवेदनशील परिस्थितियों में ट्रेन की गति नियंत्रित करने और टक्कर की आशंका को काफी हद तक कम करने में सक्षम है। रेलवे का कहना है कि नेटवर्क पर सुरक्षा, विश्वसनीयता और परिचालन क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से उच्च घनत्व और रणनीतिक महत्व वाले मार्गों पर 'कवच' प्रणाली का विस्तार लगातार किया जा रहा है।

मणिपुर : रिम्स अस्पताल परिसर में प्रदर्शन और झड़प, छोड़े गए आंसू गैस के गोले

एजेंसी, इंफाल

मणिपुर के कांगपोकपी जिले में सोमवार को हुई गोलीबारी की घटना में घायल तीन कुकी व्यक्तियों को उपचार के लिए रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) लाए जाने के बाद अस्पताल परिसर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई। विरोध प्रदर्शन धीरे-धीरे उग्र हो गया, जिसके बाद सुरक्षा बलों को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।

जानकारी के अनुसार, कांगपोकपी जिले के लेइलोन वैफेई और कोंसाखुल गांवों के निकट हुई कथित गोलीबारी में घायल तीन लोगों को विशेष उपचार के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया था। उनके अस्पताल पहुंचते ही बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी अस्पताल के मुख्य द्वार पर एकत्र हो गए और भर्ती का विरोध करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी।

स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब कुछ प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा पार कर अस्पताल परिसर में प्रवेश कर गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि घायल व्यक्ति प्रतिद्वंद्वी कुकी गुटों से जुड़े हुए हैं। इस दौरान ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन मणिपुर (एएनएसएएम) के प्रतिनिधियों ने सुरक्षा बलों द्वारा घायलों को अस्पताल तक सुरक्षा प्रदान किए जाने पर सवाल उठाए और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की।

प्रदर्शन के उग्र होने पर कुछ लोग अस्पताल के आपातकालीन वार्ड की ओर बढ़ने लगे, जिससे सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा भीड़ को तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा कर्मियों ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद प्रदर्शनकारी अस्पताल परिसर से हट गए।

हालांकि, अस्पताल के बाहर विभिन्न समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी रखा गया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए रिम्स और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। अंतिम सूचना मिलने तक इस मामले में किसी अतिरिक्त घायल या गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, जबकि प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों पर भी प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया था।

प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी ने सीबीआई चार्जशीट के ऑडियो संवाद पर किया फोकस

एजेंसी, कोलकाता

पश्चिम बंगाल के प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में डायमंड हार्बर से लोकसभा सांसद व तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सोमवार को पूछताछ कर रही है। अभिषेक निर्धारित समय से पहले साल्ट लेक स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स पहुंचे, जहां उनसे लगातार सवाल-जवाब जारी है। सूत्रों के अनुसार, ईडी की पूछताछ का आधार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की तीसरी अनुपूरक आरोपपत्र है। आरोपपत्र में वर्ष 2017 की एक कथित 15 मिनट की ऑडियो बातचीत का उल्लेख किया गया है, जिसमें कई बार "अभिषेक बनर्जी" नाम का जिक्र सामने आया था। बातचीत में कथित तौर पर नौकरी दिलाने के बदले धन लेने और उस धन के बंटवारे को लेकर चर्चा होने का दावा किया गया है।

इस मामले में पहले ही तथाकथित "कालीघाट के काकू" सुजयकृष्ण भद्र, तृणमूल के पूर्व युवा नेता शांतनु बनर्जी तथा कुंतल घोष को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियों के अनुसार, वर्ष 2017 में सुजयकृष्ण के बेहाला स्थित आवास पर इन तीनों के बीच एक बैठक हुई थी। जांच के दौरान सीबीआई को उस समय की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली थी, जिसे बाद में आरोपपत्र का हिस्सा बनाया गया। सीबीआई के अनुसार, रिकॉर्डिंग में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बड़ी राशि की मांग किए जाने की चर्चा है। आरोप है कि उम्मीदवारों से कितनी राशि एकत्र की जाएगी और वह धन किस प्रकार पहुंचाया जाएगा, इस पर बातचीत हुई थी। हालांकि, रिकॉर्डिंग में जिस "अभिषेक" का उल्लेख है, वह अभिषेक बनर्जी ही हैं या नहीं, इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

आरोपपत्र में यह भी दावा किया गया है कि कथित रिश्वत राशि नहीं मिलने पर नियुक्तियां रोकने तथा नौकरी के अभ्यर्थियों को झूठे मामलों में फंसाने जैसी धमकियों का भी उल्लेख है। बातचीत में भर्ती घोटाले के अन्य आरोपित और राज्य के पूर्व मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय का नाम भी सामने आया है।

जांच एजेंसियां सुजय कृष्ण भद्र और अभिषेक बनर्जी की कंपनी "लिप्स एंड बाउंड्स" के बीच संबंधों तथा वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही हैं। सुजयकृष्ण इस कंपनी में कर्मचारी रह चुके थे। ईडी इससे पहले भी इस कंपनी से जुड़े वित्तीय मामलों में अभिषेक से पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों का कहना है कि इस बार ईडी अभिषेक बनर्जी से उनकी अन्य कंपनियों और उनसे जुड़े वित्तीय लेनदेन के बारे में भी जानकारी जुटा सकती है। इसी कारण प्राथमिक भर्ती घोटाले के साथ-साथ कारोबारी गतिविधियां भी जांच एजेंसी के दायरे में हैं।

गौरतलब है कि, अभिषेक बनर्जी ने पहले इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए किसी भी अनियमितता में संलिप्तता से इनकार किया है। मामले की जांच जारी है और एजेंसियां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही हैं।

टीवी अभिनेत्री संचिता उगले ने की आत्महत्या, मनोरंजन जगत में शोक

एजेंसी, मुंबई

टेलीविजन जगत की जानी मानी अभिनेत्री संचिता उगले अपने घर में मृत पाई गईं हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या की है। पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है। घटना के बाद मनोरंजन जगत और उनके प्रशंसकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस के मुताबिक संचिता अपने माता-पिता और बहन के साथ मुंबई महानगर क्षेत्र के नालासोपारा में रहती थीं। घटना के समय वह घर में अकेली थीं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि उन्होंने साड़ी के सहारे फांसी लगाई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

संचिता उगले टीवी के कई चर्चित धारावाहिकों जैसे 'कुमकुम भाग्य', 'दिलवाली दूल्हा ले जाएगी' और 'साजन घर' में काम किया था। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया और हाल ही में विक्की कौशल अभिनीत फिल्म 'छावा' में 'ताराबाई' के किरदार में दिखाई दी थीं।

खास बात यह है कि मौत से कुछ घंटों पहले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक रील वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह बेहद खुश नजर आ रही थीं। उनकी अचानक मौत की खबर से फैंस स्तब्ध हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

कोलकाता होगा योगमय, हुगली नदी में 509 नौका पर होगा आयोजन

एजेंसी, नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोलकाता में 10 लाख लोगों के साथ योग करेंगे। इस वर्ष के योग दिवस की थीम "स्वस्थ आयु के लिए योग" रखा गया है। मुख्य आयोजन के साथ हुगली नदी में 509 नाव पर योग किया जाएगा। राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में सोमवार को आयोजित विशेष 'कर्टेन रेज़र' पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में योग आज एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष की विशेष थीम "स्वस्थ आयु के लिए योग" रखा गया है।

केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि इस वर्ष 21 जून को योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में रेड रोड पर होगा।

प्रताप राव जाधव कहा कि 20 जून को बंगाल दिवस भी मनाया जाएगा 19 जून को योग से ध्यान कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि कोलकाता में योग दिवस की तैयारी पूरी तेजी से चल रही है। पश्चिम बंगाल में कभी भी पिछले 50 वर्षों में योग को महत्व नहीं दिया गया जबकि बंगाल के स्वामी विवेकानंद ने योग का प्रचार प्रसार विश्व भर में किया था। इसलिए योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम इस बार कोलकाता में हो रहा है। 19 जून को कोलकाता में रन फ़ॉर योग का कार्यक्रम होगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 38 स्थानों पर योग होगा। मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के कर्तव्य पथ में होगा।

दिल्ली मेट्रो मार्गों पर मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता परीक्षण में जियो और एयरटेल आगे, एमटीएनएल और वोडाफोन -आइडिया पिछड़े

एजेंसी, नई दिल्ली

दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के राजधानी दिल्ली में मेट्रो मार्गों पर किए गए मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता परीक्षण में जियो और एयरटेल सबसे आगे रहे, जबकि एमटीएनएल और वोडाफोन-आइडिया कई मानकों पर पिछड़ गए। इस परीक्षण में जियो ने औसतन 141 एमबीपीएस और एयरटेल ने 81 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड हासिल की, जबकि एमटीएनएल 4 एमबीपीएस और वोडाफोन आइडिया 23 एमबीपीएस पर रहा। केंद्रीय संचार मंत्रालय के अनुसार अप्रैल में किए गए स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट में कवरेज गैप, कॉल ड्रॉप, कॉल सेटअप सफलता दर और डेटा स्पीड जैसे प्रमुख मानकों का आकलन किया गया। यह परीक्षण दिल्ली लाइसेंस सेवा क्षेत्र में 490 किलोमीटर लंबे मेट्रो मार्गों पर किया गया। इसमें दिल्ली मेट्रो रेल निगम, नोएडा मेट्रो रेल निगम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के मार्ग शामिल रहे।

रिपोर्ट में बताया गया कि अपलोड स्पीड में भी एयरटेल (25.98 एमबीपीएस) और जियो (19.99 एमबीपीएस) आगे रहे, जबकि एमटीएनएल (1.84 एमबीपीएस) और वोडाफोन आइडिया (16.96 एमबीपीएस) पीछे रहे। कॉल ड्रॉप दर में एमटीएनएल का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा, जहां 51 कॉल ड्रॉप दर्ज किए गए। एयरटेल में 5, जियो में 8 और वोडाफोन आइडिया में 10 कॉल ड्रॉप हुए। कवरेज गैप में भी एमटीएनएल सबसे पीछे रहा, जहां 20 हजार से अधिक नमूनों में कमजोर सिग्नल दर्ज हुआ। एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया की तुलना में एमटीएनएल का नेटवर्क प्रदर्शन सबसे कमज़ोर पाया गया।

ट्राई ने कहा कि इन परीक्षणों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को वास्तविक समय में मोबाइल नेटवर्क सेवाओं की गुणवत्ता की जानकारी देना और सेवा प्रदाताओं को अपनी सेवाओं में सुधार के लिए प्रोत्साहित करना है। परीक्षण के दौरान कवरेज, कॉल ड्रॉप दर, कॉल सेटअप सफलता दर, डेटा डाउनलोड और अपलोड स्पीड जैसे प्रमुख मानकों का आकलन किया गया। ट्राई ने बताया कि परीक्षण के दौरान एयरटेल, एमटीएनएल, जियो और वोडाफोन आइडिया की सेवाओं का मूल्यांकन किया गया। कवरेज गैप में एयरटेल के 1280, एमटीएनएल के 20768, जियो के 1297 और वोडाफोन आइडिया के 1490 नमूनों में कमजोर सिग्नल दर्ज हुआ। कॉल ड्रॉप में एयरटेल के 5, एमटीएनएल के 51, जियो के 8 और वोडाफोन आइडिया के 10 कॉल ड्रॉप दर्ज किए गए।

भारत में अनेकों गाँव शहर बन गए,पर सरकारी रिकॉर्ड में गाँव ही हैं, ऐसा क्यों? :ग्रामीण-शहरी वर्गीकरण की पुरानी व्यवस्था, मानकों पर पुनर्विचार कर संशोधन की तात्कालिक ज़रूरत -समग्र व्यापक विश्लेषण

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारत आज दुनियाँ के सबसे तेजी से शहरीकरण करने वाले देशों में शामिल है। देश के हजारों गाँव ऐसे हैं जो वास्तविकता में छोटे-बड़े शहरों का स्वरूप ग्रहण कर चुके हैं, वहाँ बहुमंजिला इमारतें, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निजी अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, बाजार, बैंकिंग सुविधाएँ, इंटरनेट कनेक्टिविटी, पक्की सड़कें और लाखों की आबादी मौजूद है। इसके बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में वे आज भी ग्राम के रूप में दर्ज हैं। इसके विपरीत कुछ क्षेत्रों में एक ही भौगोलिक क्षेत्र का एक भाग नगर परिषद अथवा नगर निगम में शामिल है जबकि दूसरा भाग ग्राम पंचायत के अधीन है। ऐसी स्थिति में एक ही क्षेत्र के नागरिकों को विकास योजनाओं बुनियादी सुविधाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के मामले में अलग-अलग व्यवहार का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति विकास नियोजन की दृष्टि से अत्यंत गंभीर विषय बन चुकी है और अब यह मांग जोर पकड़ रही है कि गाँव और शहर निर्धारित करने के मानकों की व्यापक समीक्षा की जाए। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र अधिवक्ता के तौर पर गंभीरता से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा क्रि मैंने कई शहरों में कई ऐसे स्थान देखें जहां पर रोड, नदी, नाले के इस तरफ शहर व उस तरफ गांव, जिससे वहां बिजली बिल, मकान टैक्स से लेकर जीवन शैली के हर स्टेज पर भेदभाव हो जाता है, वास्तव में किसी क्षेत्र को गाँव अथवा शहर घोषित करना केवल एक प्रशासनिक औपचारिकता नहीं है,बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं। किसी क्षेत्र का दर्जा यह तय करता है कि वहाँ विकास योजनाएँ किस प्रकार लागू होंगी, किस प्रकार का स्थानीय प्रशासन कार्य करेगा, नागरिकों को कौन-कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध होंगीकिस प्रकार के कर लगाए जाएंगे,भूमि उपयोग की नीति क्या होगी तथा आधारभूत संरचना का विकास किस दिशा में होगा। यदि कोई क्षेत्र ग्राम पंचायत के अंतर्गत है तो उस पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का प्रभाव अधिक रहता है, जबकि नगर परिषद, नगरपालिका अथवा नगर निगम क्षेत्र में शामिल होने पर शहरी विकास योजनाएँ, सीवरेज व्यवस्था,नगर परिवहन, स्मार्ट अवसंरचना औरनियोजित विकास जैसी सुविधाएँ उपलब्ध होने लगती हैं। इसलिए यदि किसी क्षेत्र की वास्तविक स्थिति और सरकारी वर्गीकरण में अंतर हो तो उसका सीधा प्रभाव नागरिकों के जीवन स्तर और विकास के अवसरों पर पड़ता है।

> » गावों में बहुमंजिला इमारतें, औद्योगिक प्रतिष्ठान, निजी अस्पताल,शैक्षणिक संस्थान, बाजार, बैंकिंग सुविधाएँ,इंटरनेट कनेक्टिविटी, पक्की सड़कें और लाखों की आबादी मौजूद,इसके बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में ग्राम के रूप में दर्ज?
>
> » संविधान के 73वें और 74वें संशोधन, अनुच्छेद 243-क्यू राज्य नगर पालिका अधिनियमों तथा जनगणना मानकों के ग्रामीण -शहरी प्रशासन के इन पारंपरिक मानकों को तात्कालिक संशोधन की जरूरत -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

साथियों, भारत में गाँव की कोई एक समान राष्ट्रीय कानूनी परिभाषा नहीं है। सामान्यतः गाँवों की पहचान राज्यों के राजस्व अभिलेखों और पंचायत कानूनों के आधार पर की जाती है। संविधान के भाग-IX तथा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है और राज्य सरकारें अपने-अपने पंचायत अधिनियमों के अनुसार गाँवों का प्रशासन संचालित करती हैं।किसी क्षेत्र को सामान्यतः तब ग्रामीण क्षेत्र माना जाता है जब वह राजस्व अभिलेखों में गाँव के रूप में दर्ज हो, ग्राम पंचायत के प्रशासनिक क्षेत्र में आता हो तथा नगर निकाय की सीमा से बाहर स्थित हो। परंतु पिछले कुछ दशकों में अनेक ऐसे गाँव विकसित हुए हैं जहाँ कृषि गतिविधियों की जगह उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र ने ले ली है, फिर भी उनका प्रशासनिक दर्जा नहीं बदला है। साथियों, भारत में शहरों का वर्गीकरण मुख्यतःदोश्रेणियों में किया जाता है,वैधानिक शहर (स्टेटुटरी टाउन) और जनगणना शहर (सेंसस टाउन)। वैधानिक शहर वे होते हैं जिन्हें राज्य सरकार किसी कानून के अंतर्गत नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका अथवा नगर पंचायत के रूप में अधिसूचित करती है। इनकी स्थापना राज्य के नगर पालिका अधिनियमों केee अंतर्गत होती है और इनके गठन का अंतिम अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। नगर निगम,नगर परिषद, नगरपालिका तथा नगर पंचायत इसी श्रेणी में आते हैं। किसी क्षेत्र की जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियों, राजस्व क्षमता और नगरीय स्वरूप को देखते हुए राज्य सरकारें ऐसे निकायों की स्थापना करती हैं।दूसरी ओर जनगणना शहर की अवधारणा भारत की जनगणना द्वारा विकसित की गई है। जनगणना के अनुसार यदि कोई क्षेत्र तीन निर्धारित मानकों को पूरा करता है तो उसे जनगणना शहर माना जाता है।

पहला, उस क्षेत्र की आबादी कम से कम 5000 होनी चाहिए। दूसरा, वहाँ जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए।तीसरा पुरुष मुख्य कार्यबल का कम से कम 75 प्रतिशत भाग कृषि के बजाय गैर-कृषि गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए। इन मानकों को 1961 कीजनगणना के दौरान प्रमुख रूप से अपनाया गया था और आज भी काफी हद तक इन्हीं का उपयोग किया जाता है। साथियों,यहीं से समस्या प्रारंभ होती है।1961 का भारत और 2026 का भारत पूरी तरह भिन्न हैं।छह दशक पहले देश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित थी, औद्योगिकीकरण सीमित था,शहर अपेक्षाकृत छोटे थे और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या का अनुपात बहुत अधिक था।आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। महानगरों का विस्तार कई किलोमीटर दूर तक हो चुका है। अनेक गाँव महानगरों के उपनगर बन चुके हैं। लाखों लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हुए प्रतिदिन शहरों में जाकर रोजगार करते हैं। सेवा क्षेत्र,सूचना प्रौद्योगिकी डिजिटल अर्थव्यवस्था और आधुनिक परिवहन ने ग्रामीण एवं शहरीe जीवन के बीच की पारंपरिक दूरी को काफी हद तक समाप्त कर दिया है। ऐसे में केवल जनसंख्या, घनत्व और गैर-कृषि रोजगार के आधार पर किसी क्षेत्र की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण करना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। साथियों, भारत के संविधान में ग्रामीण और शहरीस्थानीय निकायों के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था की गई है। वर्ष 1992 में लागू 73वें संविधान संशोधन ने पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इसके माध्यम से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसी संस्थाओं को सशक्त बनाया गया। इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत नगर पंचायत, नगरपालिका और नगर निगम जैसी संस्थाओं को संवैधानिक आधार मिला। संविधान का अनुच्छेद 243-क्यू नगर पंचायतों, नगरपालिकाओं और नगर निगमों के गठन से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य सरकारें स्थानीय परिस्थितियों, जनसंख्या, आर्थिक गतिविधियों, राजस्व क्षमता और नगरीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी क्षेत्र को शहरी निकाय के रूप में अधिसूचित कर सकती हैं। यद्यपि संविधान ने व्यापक ढाँचा उपलब्ध कराया है, फिर भी शहर घोषित करने का अंतिम अधिकार राज्यों के पास है। प्रत्येक राज्य के नगर पालिका अधिनियम में नगर पंचायत, नगरपालिका अथवा नगर निगम के गठन के लिए अलग-अलग मानदंड निर्धारित हो सकते हैं।सामान्यतः जनसंख्या जनसंख्या घनत्व, स्थानीय राजस्व, औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियाँ, नगरीय अवसंरचना तथा प्रशासनिक आवश्यकता जैसे तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। इसी कारण विभिन्न राज्यों में समान जनसंख्या वाले क्षेत्रों का दर्जा सटीक रूप से अलग-अलग हो सकता है। साथियों, जब किसी क्षेत्र का प्रशासनिक वर्गीकरण उसकी वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खाता तो अनेक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। सबसे पहली समस्या विकास निधि के आवंटन की होती है। शहर जैसी आबादी और आवश्यकताओं वाले क्षेत्रों को भी शहरी विकास योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। परिणामस्वरूप वहाँ सड़क, जल निकासी, सीवरेज, सार्वजनिक परिवहन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाओं का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता। दूसरी ओर ग्राम पंचायतों की वित्तीय और प्रशासनिक क्षमता इतनी नहीं होती कि वे तेजी से बढ़ते नगरीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसके अतिरिक्त अनियोजित निर्माण, अवैध कॉलोनियों का विकास और भूमि उपयोग संबंधी अव्यवस्था भी बढ़ जाती है।ऐसे क्षेत्रों में प्रशासनिक भ्रम भी देखने को मिलता है। कई बार एक ही सड़क के दोनों ओर अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्थाएँ लागू होती हैं। एक ओर नगर परिषद की सीमा होती है तो दूसरी ओर ग्राम पंचायत का क्षेत्र। परिणाम स्वरूप नागरिकों को कर व्यवस्था, भवन निर्माण अनुमति, जलापूर्ति, संपत्ति पंजीकरण और अन्य सेवाओं में असमानता का सामना करना पड़ता है। निवेशकों के लिए भी ऐसी स्थिति अनिश्चितता पैदा करती है, क्योंकि भूमि उपयोग और विकास नियम स्पष्ट नहीं होते।

साथियों, इस संदर्भ में यह प्रश्न भी उठता है कि क्या यह स्थिति विकासात्मक भेदभाव का उदाहरण है। कानूनी दृष्टि से इसे प्रत्यक्ष भेदभाव नहीं कहा जा सकता क्योंकि सरकारें वर्तमान कानूनों और अधिसूचनाओं के आधार पर कार्य करती हैं। फिर भी नीति निर्माण की दृष्टि से यह अवश्य कहा जा सकता है कि यदि कोई क्षेत्र वास्तविक रूप से शहरी बन चुका है और फिर भी उसे शहरी विकास योजनाओं तथा अवसंरचना निवेश से वंचित रखा जाता है तो वहाँ के नागरिक विकास के समान अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए यह स्थिति विकासात्मक असमानता का रूप सटीकता से अवश्य धारण कर लेती है। साथियों, विशेषज्ञों का मानना है कि अब गाँव और शहर के निर्धारण के लिए नए और आधुनिक मानकों की आवश्यकता है। केवल जनसंख्या और रोजगार आधारित मानक आज की जटिल सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं को नहीं दर्शाते। भविष्य में निर्मित क्षेत्र (बिल्ट- अप एरिया), भूमि उपयोग का स्वरूप, आर्थिक एकीकरण, प्रतिदिन शहरों में आने-जाने वाले लोगों की संख्या, परिवहन संपर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी, जल एवं सीवरेज सुविधाओं की उपलब्धता तथा पर्यावरणीय वहन क्षमता जैसे मानकों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे किसी क्षेत्र की वास्तविक प्रकृति का अधिक वैज्ञानिक आकलन संभव होगा।डिजिटल युग में उपग्रह चित्रों, ड्रोन सर्वेक्षण और भू-स्थानिक सूचना प्रणाली के उपयोग से यह कार्य और अधिक सरल हो सकता है। उपग्रह आधारित विश्लेषण से यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किसी क्षेत्र में निर्माण गतिविधि कितनी बढ़ चुकी है, कृषि भूमि का कितना हिस्सा शहरी उपयोग में परिवर्तित हो चुका है तथा वहाँ की जनसंख्या का घनत्व और आर्थिक गतिविधियाँ किस स्तर तक पहुँच चुकी हैं। यदि प्रत्येक पाँच वर्ष में ऐसे वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए जाएँ तो ग्रामीण और शहरी वर्गीकरण को अधिक यथार्थवादी बनाया जा सकता है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह सुधार अत्यंत आवश्यक है। आज भारत के अनेक तथाकथित गाँव आर्थिक दृष्टि से शहर बन चुके हैं,जबकि कई छोटे शहर अब महानगरीय क्षेत्रों का हिस्सा बन गए हैं। ऐसी स्थिति में 1961 के मानकों पर आधारित वर्गीकरण व्यवस्था भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं दिखाई देती। विकास संसाधनों का न्यायसंगत वितरण, नियोजित शहरीकरण, बेहतर स्थानीय प्रशासन और संतुलित क्षेत्रीय विकास तभी संभव होगा जब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की परिभाषाओं को आधुनिक वास्तविकताओं के अनुरूप पुनर्परिभाषित किया जाए। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विशेषण करें तो हम पाएंगे क्रि यह कहा जा सकता है कि भारत में गाँव और शहर के निर्धारण की वर्तमान प्रणाली ने दशकों तक प्रशासनिक स्थिरता प्रदान की है, किंतु बदलते समय में इसकी व्यापक समीक्षा अपरिहार्य हो गई है। संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन, अनुच्छेद 243-क्यू , राज्य नगर पालिका अधिनियमों तथा जनगणना मानकों ने अब तक ग्रामीण- शहरी प्रशासन की आधारशिला रखी है, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि इन पारंपरिक मानकों के साथ आधुनिक तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक संकेतकों को भी जोड़ा जाए। तभी भारत के वास्तविक शहरीकरण को सही पहचान मिल सकेगी और विकास का लाभ प्रत्येक नागरिक तक समान रूप से पहुँच सकेगा।

-संकलनकर्ता लेखक - क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318

घरेलू महिलाओं को भी है, आर्थिक मजबूती की जरूरत

लेखिका--डॉ. अंशुल उपाध्याय

भारत मे घरेलू महिलाओं को भी आर्थिक सबलता का अधिकार प्राप्त होना चाहिये।वे महिलाये जो नोकरी पेशा नही है।और घर पर रहकर ही अपने बच्चो और परिवार के पोषण के लिये अपना सारा समय लगा देती है।उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उनके पति के द्वारा कुछ धनराशि प्रति माह प्राप्त होनी ही चाहिए। इससे न केवल महिलाओं को सबलता मिलेगी बल्कि घरेलू हिंसा के मामलो में भी कमी आएगी। भारत मे लगभग घरेलू दायरे में हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है। किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारिवारिक सम्बन्ध हैं, घरेलू हिंसा में शामिल है। "घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम की धारा, 2005" घरेलू हिंसा को पारिभाषित किया गया है "प्रतिवादी का कोई बर्ताव, भूल या किसी और को काम करने के लिए नियुक्त करना, घरेलू हिंसा में माना जाएगा। क्षति पहुँचाना या जख्मी करना या पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य, जीवन, अंगों या हित को मानसिक या शारीरिक तौर से खतरे में डालना या ऐसा करने की नीयत रखना और इसमें शारीरिक, यौनिक, मौखिक और भावनात्मक और आर्थिक शोषण शामिल है; या दहेज़ या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए महिला या उसके रिश्तेदारों को मजबूर करने के लिए यातना देना, नुक्सान पहुँचाना या जोखिम में डालना ; या पीड़ित या उसके निकट सम्बन्धियों पर उपरोक्त वाक्यांश (क) या (ख) में सम्मिलित किसी आचरण के द्वारा दी गयी धमकी का प्रभाव होना; या पीड़ित को शारीरिक या मानसिक तौर पर घायल करना या नुक्सान पहुँचाना" सर्वेक्षण में पाया गया है कि 32% विवाहित महिलाओं (18-49 वर्ष) ने शारीरिक, यौन या भावनात्मक वैवाहिक हिंसा का अनुभव किया है। वैवाहिक हिंसा का सबसे आम प्रकार शारीरिक हिंसा (28%) है, जिसके बाद महिलाओं के साथ भावनात्मक हिंसा और यौन हिंसा हुई है।महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा के 80% से अधिक मामलों में अपराधी पति होता है। जिन पतियों ने स्कूली शिक्षा के 12 या अधिक वर्ष पूरे कर लिए हैं, उनमें शारीरिक, यौन, या भावनात्मक वैवाहिक हिंसा करने की संभावना आधी (21%) होती है। जबकि स्कूली शिक्षा न पूरी करने वाले 43% लोग हिंसा में संलिप्त होते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण भारत सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ज़्यादा पढ़ी-लिखी महिलाओं को अपने पति से घरेलू हिंसा का खतरा कम पढ़ी-लिखी की तुलना में 1.54 गुना ज़्यादा होता है। एक गैर सरकारी संस्था के मुताबिक, भारत में लगभग पांच करोड़ महिलाओं को अपने घर में ही हिंसा का सामना करना पड़ता है। इनमें से मात्र 0.1 प्रतिशत ही हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आगे आती हैं। एनएफएचएस की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विवाहित कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत 31%(एनएफएचएस - 4), से 32% के बीच हैं। 2019-2021, नई NHFS - 5 रिपोर्ट 12 मई 2022 के अनुसार भारत मे 92% महिलाये बिना मेहनताना लिये घरेलू काम करती हैं जबकि सिर्फ 27% पुरूष ही ऐसा करते है। भारतीय महिलाओ को जो नौकरी पेशा नही है। अपने पति द्वारा प्रति माह कुछ धनराशि अवश्य दी जानी चाहिए, इससे ना केवल घरेलू हिंसा के मामलों में बल्कि महिलाओ के मानसिक तनावो में भी कमी आयेगी। कुछ महिलाएं जो पढ़ी लिखी है मगर नौकरी पेशा नही है उन्हें हर वक़्त ये बात कचोड़ती तो अवश्य होगी की काश वो भी औरो की तरह अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए ही सही कुछ रुपए कमा सकती। चूंकि शिक्षा का व्यक्ति के मानसिक विकास मे महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मानसिक विकास हो जाने के बाद व्यक्ति अपना अच्छा बुरा स्वयम समझ पाता है। ऐसे मे किसी मानसिक रूप से विकसित महिला का घर पर रहना कई बार उसकी मजबूरी होती हैं।

जयपुर में गूंजे थप्पड़, लेकिन सवाल पूरे देश से:

एजाज़ अहमद उस्मानी की क़लम से

> » आखिर युवाओं का गुस्सा किस ओर जा रहा है?

नीट पेपर लीक, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक टकराव के बीच शहीद स्मारक पर हुई घटना ने कई गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। जयपुर के शहीद स्मारक पर सोमवार का दिन सामान्य नहीं था। वहां मौजूद सैकड़ों युवाओं की आंखों में अपने भविष्य को लेकर चिंता थी, हाथों में तख्तियां थीं और जुबान पर व्यवस्था के खिलाफ सवाल थे। मंच से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठ रही थी, नीट पेपर लीक के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की जा रही थी। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे प्रदर्शन का केंद्र बदल दिया। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को दो युवकों ने सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मार दिए। घटना के बाद माहौल अचानक गरमा गया। समर्थकों ने हमलावर युवकों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। कुछ मिनटों की यह घटना सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन गई। लेकिन इस घटना को केवल एक राजनीतिक विवाद या मारपीट की घटना मान लेना शायद सबसे बड़ी भूल होगी। यह घटना दरअसल उस बेचैनी, निराशा और आक्रोश की झलक है जो आज देश के लाखों युवाओं के भीतर कहीं न कहीं पल रहा है। जब सपनों पर लगते हैं प्रश्नचिह्न भारत दुनिया का सबसे युवा देश कहलाता है। यहां करोड़ों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई शिक्षक तो कोई प्रशासनिक अधिकारी। इन सपनों को पूरा करने के लिए परिवार अपनी जमा-पूंजी तक खर्च कर देते हैं। लेकिन जब वर्षों की मेहनत के बाद कोई परीक्षा पेपर लीक की भेंट चढ़ जाए, भर्ती प्रक्रिया अदालतों में उलझ जाए या नियुक्तियां वर्षों तक अटक जाएं, तब केवल एक परीक्षा नहीं टूटती, बल्कि हजारों-लाखों युवाओं के सपने भी बिखर जाते हैं। नीट पेपर लीक जैसे मामलों ने युवाओं के मन में यह सवाल पैदा कर दिया है कि क्या उनकी मेहनत वास्तव में सुरक्षित है? क्या ईमानदारी से पढ़ने वाले छात्र और छात्राएं उस व्यवस्था में न्याय पा सकेंगे जहां कुछ लोग पैसे और प्रभाव के दम पर नियमों को तोड़ देते हैं?

यही सवाल सोमवार को जयपुर के शहीद स्मारक पर भी सुनाई दे रहे थे।

गुस्सा आखिर किस पर है?- जब कोई युवा सड़क पर उतरता है तो उसका उद्देश्य केवल नारे लगाना नहीं होता। वह अपनी आवाज सत्ता तक पहुंचाना चाहता है। वह चाहता है कि उसकी समस्या को गंभीरता से सुना जाए।

लेकिन जब समस्याओं का समाधान लंबे समय तक नहीं निकलता, तब गुस्सा बढ़ता जाता है। यही गुस्सा कभी सोशल मीडिया पर दिखता है, कभी धरनों में और कभी दुर्भाग्यवश हिंसक घटनाओं का रूप ले लेता है।

अभिजीत दीपके पर हमला करने वाले युवकों ने चाहे जो सोचकर यह कदम उठाया हो, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी असहमति का जवाब हाथ उठाकर नहीं दिया जा सकता। वहीं दूसरी ओर समर्थकों द्वारा की गई मारपीट भी यह बताती है कि समाज में धैर्य और संवाद की जगह धीरे-धीरे कम होती जा रही है।

लोकतंत्र की असली ताकत क्या है?- लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहां किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप किसी नेता, संगठन, विचारधारा या आंदोलन से सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। लेकिन असहमति का सबसे मजबूत हथियार तर्क होता है, थप्पड़ नहीं। जब किसी विचार का जवाब हिंसा से दिया जाता है तो वह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं होता, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी चोट होती है। इतिहास गवाह है कि बड़े-बड़े परिवर्तन संवाद, विचार और जनशक्ति से आए हैं। हिंसा ने कभी स्थायी समाधान नहीं दिया।

युवाओं की पीड़ा को समझना होगा- आज देश का युवा केवल नौकरी नहीं मांग रहा। वह अवसर मांग रहा है। वह पारदर्शिता मांग रहा है। वह चाहता है कि उसकी मेहनत का सम्मान हो।

एक छात्र जो रात-रात भर जागकर पढ़ाई करता है, जब पेपर लीक की खबर सुनता है तो उसका आत्मविश्वास टूटता है। एक बेरोजगार युवक जो वर्षों तक तैयारी करता है, जब भर्ती प्रक्रिया अटकती देखता है तो उसका धैर्य टूटता है। यही टूटन धीरे-धीरे आक्रोश में बदल जाती है। इसलिए जरूरत केवल कानून-व्यवस्था संभालने की नहीं है, बल्कि उन कारणों को समझने की है जो युवाओं को इतना बेचैन कर रहे हैं।

सोशल मीडिया का दौर और बढ़ती कटुता- आज का समय सोशल मीडिया का समय है। कोई भी घटना कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। वीडियो वायरल होते हैं, बहसें शुरू हो जाती हैं और लोग अपने-अपने पक्ष में खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस तेज़ी के दौर में संवाद की जगह अक्सर आरोप-प्रत्यारोप ले लेते हैं। लोग एक-दूसरे को सुनने के बजाय केवल जवाब देने में लगे रहते हैं। जयपुर की घटना भी इसी प्रवृत्ति का हिस्सा बनती दिखाई देती है, जहां कुछ मिनटों की घटना ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है।

सवाल केवल अभिजीत दीपके का नहीं है- यह मामला केवल एक व्यक्ति या एक संगठन तक सीमित नहीं है। यह सवाल उस पूरे माहौल का है जिसमें युवा अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा है। यह सवाल उन माता-पिताओं का भी है जो अपने बच्चों के सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह सवाल उस शिक्षा व्यवस्था का है जिसे देश के भविष्य की नींव माना जाता है। और यह सवाल उन नेताओं और नीति-निर्माताओं का भी है जिनके हाथों में आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है।

देश को किस दिशा में जाना है?

क्या हम ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जहां मतभेद का जवाब थप्पड़ से दिया जाए?

क्या हम ऐसा माहौल चाहते हैं जहां किसी भी मुद्दे पर बातचीत की जगह टकराव ले ले?

या फिर हम ऐसा लोकतंत्र चाहते हैं जहां हर आवाज सुनी जाए, हर सवाल का जवाब मिले और हर युवा को यह भरोसा हो कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी?

इन सवालों का जवाब केवल सरकारों को नहीं देना है, बल्कि पूरे समाज को देना है।

थप्पड़ों से ज्यादा गूंज रहे हैं सवाल- जयपुर के शहीद स्मारक पर गूंजे थप्पड़ों की आवाज कुछ ही क्षणों में थम गई होगी, लेकिन उस घटना ने जो सवाल खड़े किए हैं, वे लंबे समय तक चर्चा का विषय बने रहेंगे।

देश का युवा गुस्से में क्यों है?

उसके सपनों पर बार-बार संकट क्यों खड़े हो रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण—क्या हम उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक जयपुर की यह घटना केवल एक समाचार नहीं रहेगी, बल्कि उस बेचैनी का प्रतीक बनी रहेगी जो आज लाखों युवाओं के दिलों में पल रही है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति होती है। यदि वही शक्ति निराश, क्रोधित और असंतुष्ट हो जाए, तो यह केवल युवाओं की नहीं, पूरे देश की चिंता का विषय बन जाता है।

सड़क हादसों में जा रहीं हैं हर घंटे बीस जिंदगी

लेखक - मनोज कुमार अग्रवाल

भारत में सड़क हादसों के कारण हर साल औसतन 1.80 लाख लोगों की मौत होती है। सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, एक साल में देशभर में 4.80 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें हर घंटे औसतन 20 लोगों की जान चली जाती है। भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024 में सड़क दुर्घटनाओं में 1,77,175 लोगों की मौत हुई है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि देश में औसतन हर दिन लगभग 485 लोग और हर घंटे 20 से अधिक लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों का ग्राफ लगातार बढ़ा है देशभर में 4,87,707 सड़क हादसे दर्ज किए गए। इन हादसों में 1,77,175 लोगों ने जान गंवाई, जो 2023 (1,72,890 मौतें) के मुकाबले 2.5% अधिक है। साल 2024 में इन दुर्घटनाओं के कारण 4,71,441 लोग घायल हुए हैं विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में विशेष रूप से गरीब और विकासशील देशों के लोगों की संख्या में अविश्वसनीय वृद्धि हुई है और इनमें से भी प्रत्येक 5 में से 1 मौत भारत में होती है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में हर घंटे होने वाली लगभग 56 सड़क दुर्घटनाओं में 20 लोगों की जान जाती है। इसी कारण भारत को सड़क दुर्घटनाओं की राजधानी भी कहा जाने लगा है। स्थिति की गंभीरता पिछले मात्र दो तीन दिन की अखबारों में प्रकाशित हादसों की खबरों से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है :5 जून को वैष्णो देवी से श्रद्धालुओं को लेकर आ रही एक पिक-अप गाड़ी और ट्रक की टक्कर में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई।6 जून को फिरोजपुर-फाजिल्का रोड पर गांव जंगाला मोड़ के निकट एक पिकअप गाड़ी तथा घोड़ा ट्राले में टक्कर के परिणामस्वरूप 10 लोगों की मौत तथा अनेक घायल हो गए।

7 जून को रोपड़ (पंजाब) जिले में भारतगढ़ के निकट एक कार सड़क के किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। 7 जून को ही शाहाबाद-पिपली जी.टी. रोड पर एक बेकाबू ट्राले ने एक मोटरसाइकिल को चपेट में ले लिया जिससे उस पर सवार मोहाली नगर निगम के 2 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई।

8 जून को औरंगाबाद (बिहार) में 4 सड़क दुर्घटनाओं में 9 लोगों की जान चली गई तथा अनेक घायल हो गए।

8 जून को ही फगवाड़ा में एक मोटरसाइकिल, 2 कारों और एक ट्रक की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार और उसकी 7 वर्षीय बेटी की घटनास्थल पर ही मौत तथा उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई।

9 जून को शंभू (राजपुरा, पंजाब) में एक ट्रक ड्राइवर ने 2 लोगों को रौंद डाला जिनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

9 जून को ही चहेड़ (फगवाड़ा, पंजाब) में एक्टिवा पर सवार 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी जिससे दोनों की मौत हो गई।

9 जून को ही लुधियाना (पंजाब) में एक कंटेनर के चालक ने तेज रफ्तार से उसे बैंक करने की कोशिश में एक मजदूर को रौंद दिया।

10 जून को देहरादून (उत्तराखंड) में झाड़पानी क्षेत्र में एक कार के गहरी खाई में गिर जाने से उसमें सवार 4 लोगों की मौत हो गई।

10 जून को ही बेगोवाल (पंजाब) में सड़क दुर्घटना में एक कार बेकाबू हो कर पेड़ से टकरा गई जिससे एक दम्पति की मृत्यु हो गई।

10 जून को ही भीखी (पंजाब) में एक ट्राले की टक्कर ट से बाइक रेहड़े पर सवार 2 दोस्तों की जान चली गई।

11 जून को पुणे (महाराष्ट्र) में नवाले पुल से नीचे उतरते समय एक सीमेंट मिक्सर ट्रक बेकाबू होकर मोटरसाइकिल पर जा रहे एक डिलीवरी ब्वाय से टकरा गया जिससे उसकी मौत हो गई। 11 जून को ही गाँडा (उत्तर प्रदेश) में 2 मोटरसाइकिलों की टक्कर में घायलों की मदद करने पहुंचे लोगों को तेज रफ्तार एस.यू. वी. ने रौंद दिया जिससे 4 लोगों की मौत व 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।11 जून को ही फिरोजपुर (पंजाब) में मोटरसाइकिल पर जा रहे 3 युवकों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी जिससे उनकी मौत हो गई। 11 जून को ही पोत्थरैड्डीपालम (आंध्र प्रदेश) में एक कार बेकाबू होकर एक मकान से जा टकराई जिससे कार में सवार 5 मैडिकल के छात्रों सहित 6 लोगों की जान चली गई।

ऋचा घोष ने 200 के स्ट्राइक रेट से पारी खेली

बड़ा कीर्तिमान बना, भारत का टी20 वर्ल्ड कप में तीसरा सर्वोच्च स्कोर

नई दिल्ली। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ रविवार (14 जून) को भारत ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। उप-कप्तान स्मृति मंधाना की अर्धशतकीय पारी के अलावा ऋचा घोष ने 200 के स्ट्राइक रेट से पारी खेलकर बड़े स्कोर तक पहुंचाया। ऋचा ने 17 गेंद पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 34 रन बनाए। वह जब क्रीज पर आईं तब भारतीय टीम

की हालत खराब थी। उसने 14.2 ओवर में 110 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। इस तूफानी बल्लेबाजी के कारण ऋचा घोष के नाम भारत के लिए टी20 वर्ल्ड कप में नंबर 6 या नीचे बल्लेबाजी करते हुए सर्वोच्च स्कोर हो गया। उनकी इस पारी के दम पर भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में अपना तीसरा सर्वोच्च स्कोर बनाया। भारत ने 2018 न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट पर 194 रन बनाए थे। यह उसका सर्वोच्च स्कोर है। उसने श्रीलंका के खिलाफ 2024 में 3 विकेट पर 172 रन बनाए। यह भारत का टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ सर्वोच्च स्कोर भी है।

विश्वकप में भारत का बड़े स्कोर

- 194/5 बनाम न्यूजीलैंड, प्रोविडेंस, 2018
- 172/3 बनाम श्रीलंका, दुबई, 2024
- 170/6 बनाम पाकिस्तान, बर्मिंघम, 2026
- 167/8 बनाम ऑस्ट्रेलिया, प्रोविडेंस, 2018
- 167/8 बनाम ऑस्ट्रेलिया, केपटाउन, 2023

जर्मनी ने तोड़ा ब्राजील का विश्व रिकॉर्ड

कुराकाओ को 7-1 से हराकर रच दिया इतिहास

नई दिल्ली। दुनिया की बेहतरीन टीमों में शुमार जर्मनी ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अपनी शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की और इस सीजन में डेब्यू करने वाली टीम कुराकाओ को 7-1 के बड़े अंतर से हरा दिया। इस जीत के साथ जर्मनी ने ना सिर्फ 3 अंक हासिल किए बल्कि फुटबॉल वर्ल्ड कप इतिहास में एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जो पहले ब्राजील के नाम पर दर्ज था।

ग्रुप ई में हुए इस मुकाबले में जर्मनी की टीम शुरुआत से ही कुराकाओ पर पूरी तरह से हावी नजर आई और इस टीम ने वैसा ही खेल दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जर्मनी में किसी भी पल इस मैच में विरोधी टीम को जरा सा भी खुद पर हावी नहीं होने दिया और 7-1 के अंतर से उसे हराया और साल 2014 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की याद ताजा करवा दी जिस मुकाबले में जर्मनी ने ब्राजील को 7-1 से हराया था।

जर्मनी को बड़े अंतर से मिली जीत

इस मैच में कुराकाओ के खिलाफ जर्मनी ने बेहद तेज अंदाज में शुरुआत की। छठे मिनट में फेलिक्स नेमेचा ने शानदार गोल दागकर टीम को बढ़त दिलाई। हालांकि 21वें मिनट में कुराकाओ ने बराबरी का गोल दागते हुए स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद जर्मनी ने मैच पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। 38वें मिनट में निको श्लॉटरबेक ने कॉर्नर पर शानदार हेडर लगाकर टीम को बढ़त वापस दिलाई। हाफ टाइम से ठीक पहले काई हैवर्ट्ज ने पेनल्टी को गोल में बदलकर स्कोर 3-1 कर दिया। दूसरे हाफ की शुरुआत के सिर्फ 69 सेकेंड बाद ही जमाल मुसियाला ने गोल दागकर मुकाबला लगभग समाप्त कर दिया। इसके बाद नाथानियल ब्राउन, डेनिज उंडाव और काई हैवर्ट्ज ने गोलों की बरसात जारी रखी और जर्मनी ने 7-1 के अंतर से मैच जीत लिया।

वर्ल्ड कप इतिहास में में जर्मनी ने 239 गोल हो गए

कुराकाओ के खिलाफ 7 गोल दागने के साथ ही जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाली टीम बन गई। जर्मनी के अब फुटबॉल वर्ल्ड कप में कुल 239 गोल हो गए जबकि ब्राजील 238 गोल के साथ दूसरे नंबर पर आ गया। वहीं फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना है जिसके 152 गोल हैं। यही नहीं ये चौथा मौका है जब जर्मनी ने किसी वर्ल्ड कप मैच में 7 या उससे ज्यादा गोल दागे हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड हंगरी के नाम था, जिसने तीन बार ऐसा कमाल किया था।

आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया

अमाद डियालो ने अंतिम क्षणों में किया गोल

फिलाडेल्फिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के विंगर अमाद डियालो के 90वें मिनट में किए गए गोल की मदद से आइवरी कोस्ट ने सोमवार को फिलाडेल्फिया स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ई के रोमांचक मैच में इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला गोलरहित ड्रॉ पर समाप्त होगा, लेकिन सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी के तौर पर आए अमाद ने शानदार शॉट लगाते हुए आइवरी कोस्ट को 2014 के बाद विश्व कप में पहली जीत दिलाई। इस जीत से आइवरी कोस्ट ग्रुप ई में जर्मनी के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। रविवार को कुराकाओ को 7-1 से हराने के बाद जर्मनी पहले स्थान पर है। मैच के पहले हाफ में इक्वाडोर ने कई अच्छे मौके बनाए। जॉन येबोआ का एक दमदार शॉट क्रॉसबार से टकरा गया और गोल नहीं हो सका। इसके कुछ ही समय बाद एलन मिंडा भी गोल करने के करीब पहुंचे, लेकिन उनका शॉट भी बार से टकराकर बाहर चला गया। इस तरह इक्वाडोर शुरुआती बढ़त हासिल करने का मौका गंवा बैठा।

दूसरी ओर, आइवरी कोस्ट ने भी कुछ खतरनाक हमले किए। यान डियोमांडे ने दाएं छोर से शानदार खेल दिखाया और लगातार विपक्षी डिफेंस पर दबाव बनाया। वहीं, बाजूमाना टूरे के एक तेज शॉट को इक्वाडोर के गोलकीपर हर्नान गैलिंडेज ने बेहतरीन बचाव करते हुए गोल में जाने से रोक दिया। इस मैच में यान डियोमांडे ने एक खास उपलब्धि भी हासिल की। 19 साल और 212 दिन की उम्र में वह आइवरी कोस्ट के लिए वर्ल्ड कप मैच खेलने वाले पहले किशोर खिलाड़ी बने।

व्यापार

चांदी 7,200 उछली, सोना भी 3,300 महंगा

नई दिल्ली, एजेंसी। सोने और चांदी की कीमत में आज लगातार तीसरे दिन तेजी आई है। अमेरिका और ईरान तीन महीने से भी लंबे समय से चले आ रहे युद्ध को खत्म करने के लिए सहमत हो गए हैं। इससे कच्चे तेल की कीमत में गिरावट आई है। इसका असर सोने और चांदी पर देखने को मिल रहा है। इससे एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में सोना 3,300 रुपये महंगा हो गया जबकि चांदी की कीमत में 7,200 रुपये की तेजी आई है। तीन दिन में चांदी 18,000 रुपये महंगी हुई है जबकि सोने की कीमत में 6,000 रुपये की तेजी आई है। एमसीएक्स पर 5 अगस्त की डिलीवरी वाला सोना पिछले सत्र में 1,50,528 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था और आज यह 1,53,829 रुपये पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 3,301 रुपये की तेजी के साथ 1,53,829 रुपये तक पहुंचा। सुबह 10.10 बजे यह 2717 रुपये यानी 1.80 फीसदी तेजी के साथ 1,53,245 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। चांदी की कीमत में भी आज तेजी आई है। एमसीएक्स पर 3 जुलाई की डिलीवरी वाली चांदी पिछले सत्र में 2,46,186 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुई थी और आज यह 2,51,563 रुपये पर खुली। शुरुआती कारोबार में यह 7,159 रुपये की तेजी के साथ 2,53,345 रुपये तक उछली।

मजाक है यूएस हेल्थकेयर सिस्टम, अमेरिका में जो दवा 95,000 की, भारत में उसी का रेट सिर्फ 2,300

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिका और भारत में दवाओं की कीमतों में फर्क हैरान करने वाला है। इसकी तुलना एक अमेरिकी महिला ने की है। इसने हेल्थकेयर की लागत को लेकर ऑनलाइन बहस छेड़ दी है। महिला ने बताया कि अमेरिका में जिस दवा की कीमत 1,000 डॉलर (लगभग 95,000 रुपये) बताई गई थी। वही दवा भारत से मंगाने पर उन्हें सिर्फ 25 डॉलर (लगभग 2,300 रुपये) में मिली। इंस्टाग्राम पर विक्टोरिया नाम से पहचानी जाने वाली इस महिला ने एक वीडियो में अपना अनुभव साझा किया है। यह वीडियो अब खूब शेयर हो रहा है। उन्होंने कीमतों में इस भारी अंतर को हेल्थकेयर सिस्टम की बड़ी खामियों का सबूत बताया।

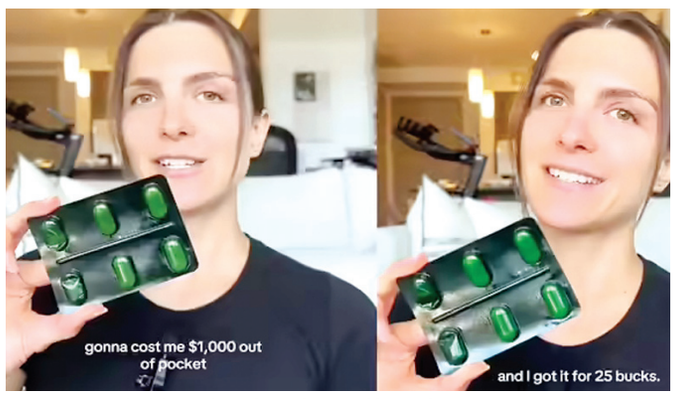

वीडियो में उन्होंने कहा, 'अमेरिका में इस दवा के लिए मुझे अपनी जेब से 1,000 डॉलर खर्च करने पड़ते। लेकिन, मैंने इसे 25 डॉलर में खरीदा। हां, सिर्फ छह छोटी गोलियों के लिए 1,000 डॉलर अपनी जेब से देने पड़ते क्योंकि मेरा इंश्योरेंस इसे कवर नहीं कर रहा था।' इतनी बड़ी रकम खर्च न करने के इरादे से विक्टोरिया ने अपने डॉक्टर से दूसरे विकल्पों के बारे में बात की। उनके अनुसार, डॉक्टर ने सुझाव दिया कि वह कनाडा की एक फार्मेसी को प्रिस्क्रिप्शन भेजें, जो सीधे भारत के मैन्युफैक्चरर से दवा मंगा सकती थी। उन्हें उम्मीद थी कि खर्च फिर भी सैकड़ों डॉलर होगा। लेकिन, जो कीमत उन्हें बताई गई, उसे सुनकर वे हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, 'कीमत 25 डॉलर थी। 10 डॉलर दवा के लिए और 15 डॉलर शिपिंग के लिए। भारत में मैन्युफैक्चरर से सीधे मेरे पास इंटरनेशनल शिपिंग।'

भारत की जेनरिक दवा इंडस्ट्री को दिया श्रेय: यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो गया, जहां कई यूजर्स ने अमेरिकी हेल्थकेयर सिस्टम को लेकर उनकी निराशा का समर्थन किया। कुछ लोगों ने भारत की बड़ी जेनेरिक दवा इंडस्ट्री की ओर इशारा किया। इसने कई दवाओं को काफी सस्ता बनाने में मदद की है। कई लोगों ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत में जो दवाएं लगभग 150 रुपये में मिल जाती हैं, वे विदेशों में कई गुना महंगी हो सकती हैं।

इससे दुनिया भर में हेल्थकेयर की कीमतों, इंश्योरेंस कवरेज और सस्ते इलाज तक पहुंच को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है।

1000 डॉलर की दवा 25 डॉलर में खरीदी

दवा दिखाते हुए विक्टोरिया ने बताया कि उन्हें सिर्फ छह गोलियों की जरूरत थी। लेकिन, उन्हें बताया गया कि इसके लिए उन्हें अपनी जेब से 1,000 डॉलर खर्च करने होंगे। कारण है कि उनके इंश्योरेंस प्रोवाइडर ने इस दवा का खर्च उठाने से मना कर दिया था। इस अनुभव ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अमेरिका में उसी दवा की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है। अमेरिकी हेल्थकेयर सिस्टम को 'मजाक' बताते हुए विक्टोरिया ने कहा, 'हमारे साथ पूरी तरह से धोखा हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि इसकी कीमत एक हजार डॉलर होने वाली थी जबकि मैं दवा के लिए सिर्फ 10 डॉलर दे पाई।' उन्होंने आगे यह भी सोचा कि बाकी पैसे कहां जा रहे हैं। तर्क दिया कि आम मरीजों को अक्सर हेल्थकेयर की बढ़ी हुई लागत का बोझ उठाना पड़ता है।

जिस रास्ते पर 100 दिन से सन्नाटा था, वहां सबसे पहले दिखा भारतीय एलएनजी टैंकर, अमेरिका-ईरान डील का असर

नई दिल्ली, एजेंसी। अमेरिकी-ईरान के बीच शांति समझौता होने से भारत को भी बड़ी राहत मिलेगी। इस समझौते के बाद मुख्य ईंधन मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य भी खुल जाएगा। पिछले तीन महीनों से अधिक समय से फारस की खाड़ी में फंसा भारत का एक लिक्विफाइड नेचुरल गैस टैंकर अब होर्मुज की ओर बढ़ता दिख रहा है। इस टैंकर का नाम दिशा है। डील के बाद होर्मुज खुलने से यहां से गुजरने वाला यह पहला टैंकर होगा। शिपिंग कंपनियों के मालिक इस खबर का आकलन कर रहे हैं और समझौते की बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस समझौते की पूरी डिटेल आने में अभी कुछ दिन लग सकते हैं। यही वजह है कि सोमवार के शुरुआती घंटों में इस समुद्री कॉरिडोर के आसपास जहाजों की आवाजाही न के बराबर देखी गई। हालांकि, भारतीय टैंकर 'दिशा' ने इस दिशा में पहला कदम बढ़ाया है। एक चुनौती यह भी है कि जहाजों द्वारा अपनी सही लोकेशन छिपाने और अपने ट्रांसपोंडर (लोकेशन बताने वाला सिस्टम) बंद करके जलमार्ग पार करने की घटनाओं के कारण वास्तविक स्थिति पर नजर रखना काफी मुश्किल हो गया है। यहां तक कि जो

जहाज दिखाई दे रहे हैं, उनमें से भी कई ने पिछले कुछ दिनों या हफ्तों से अपनी लोकेशन का कोई सिग्नल नहीं दिया है। होर्मुज से आवाजाही दोबारा शुरू होने से मार्च से यूरोप और एशिया में गैस की बढ़ी हुई कीमतों और सप्लाई की किल्लत से बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही कच्चे तेल के बाजार में भी गिरावट आई और ब्रेंट क्रूड शुरुआती कारोबार में 4 फीसदी से ज्यादा टूट गया। ब्लूमबर्ग की ओर से जुटाए गए शिप-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, भारत की एक सरकारी आयातक कंपनी द्वारा लॉन्ग-टर्म लीज पर लिया गया यह एलएनजी जहाज संयुक्त अरब अमीरात के उत्तर में है और ओमान के करीब पहुंच रहा है। आसपास कतर की रास लफ्फान फैसिलिटी से गैस की खेप लोड की थी। बेहद महत्वपूर्ण माना जाने वाला 'होर्मुज जलमार्ग' फरवरी के अंत में अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद से पूरी तरह बंद है।

वैश्विक बाजार के लिए बड़ी राहत

इस रणनीतिक कॉरिडोर से रुकावट हटाने और दोनों तरफ से लगी नाकेबंदी को खत्म करने का यह समझौता आयातकों और वैश्विक बाजार के लिए एक बड़ी राहत है। हालांकि, जमीन पर इसे लागू करने में कई मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि इस जलमार्ग पर ईरान का मजबूत नियंत्रण उसे एक बड़ा फायदा देता है। अब बाजार के कारोबारियों और जहाज मालिकों की नजरें जलमार्ग के दोनों ओर दुबई और ओमान की खाड़ी में लंगर डाले खड़े जहाजों के समूहों पर टिकी हैं, जो हरी झंडी मिलते ही तेजी से आगे बढ़ सकते हैं।

8वें पे कमीशन से जुड़ी जरूरी डेडलाइन, चूक गए तो 10 साल बाद मिलेगा मौका

नईदिल्ली, एजेंसी। 8वें पे कमीशन जुड़ी एक अहम डेडलाइन आज है। कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों को आयोग ने 15 जून 2026 तक मेमोरेंडम जमा करने का समय दिया था। पे कमीशन की तरफ से कई बार डेडलाइन को आगे बढ़ाया गया है। इस बार उम्मीद कम ही है कि फिर से आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया जाए। बता दें, सभी स्टेकहोल्डर्स के पास आज यानी 15 जून रात्रि 12 बजे तक अपनी डिमांड आयोग को देना होगा।

पे कमीशन की तरफ से कहा गया है कि पीडीएफ, फिजिकल ईमेल्स और हार्ड कॉपी नहीं जमा किया जाएगा। आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि प्रपोजल को तय मानक में देने पर ही स्वीकारा जाएगा।

इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन ने कम से कम बेसिक पे 52600 रुपये करने की मांग की है। कई कर्मचारी संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर को 2.92 से 3.50 करने की मांग की है। अगर ऐसा होता है कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा होगा। 8वां पे कमीशन देश के अलग-अलग हिस्सों में कई बड़ी मीटिंग्स कर रहा है। इन मीटिंग्स में कर्मचारी संगठन और उनसे जुड़े सभी पक्षों से बातचीत की जा रही है। लखनऊ में पे कमीशन की मीटिंग 22 और 23 जून 2026 को होगी। भुवनेश्वर में मीटिंग 6 से 7 जुलाई 2026 को होगी। वहीं, कोलकाता में मीटिंग 7 से 9 जुलाई 2026 को प्रस्तावित है। इससे पहले जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में 8वें वित्त आयोग की मीटिंग्स हो चुकी हैं। 7वें पे कमीशन के गठन और उसके लागू होने तक 21 महीने तक का समय लग गया था।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593 RNI No.: DELHIN/2008/23928
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM
किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।
क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)